



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, 20 दिसम्बर, 1975/अग्रहायण 29, 1897  
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 20, 1975/AGRAHAYANA 29, 1897

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

### भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)  
केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India  
(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities  
(other than the Administrations of Union Territories)

#### विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1975

का० आ० 5283.—का०आ० 523 (इ) केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 58 क की उपधारा (7) के खंड (ख) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, सभी वर्गों की वित्तीय कम्पनियों को ऐसी कम्पनियों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिन्हें कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क का कोई उपबन्ध (उस धारा की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधिनियम से संबंधित उपबन्धों को छोड़ कर), उस खंड के प्रयोजनार्थ लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण:—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, 'वित्तीय कम्पनी', से अभिप्रेत है ऐसी अवैकारी कम्पनी जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-1 के खंड (ग) के अर्थों के अनुसार वित्तीय संस्था है।

[संख्या 1/21/75-सी० एल० 14]

का० आ० 5284.—का०आ० 524 (इ) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642क साथ पठित धारा 58क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक

के परामर्श से, कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम, 1975 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) संशोधन नियम, 1975 है।

\*(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 1 के उपनियम (3) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायगा, अर्थात् "परन्तु नियम 4 के सिवाय, इन नियमों की कोई बात उस अवैकारी कम्पनी को लागू नहीं होगी जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 क के खंड (ग) के अर्थ में वित्तीय संस्था है।"

3. उक्त नियमों के नियम 2 के खंड (ख) में उपखंड (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात्:—

"(ix) किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त कोई रकम जो उक्त रकम की प्राप्ति के समय कम्पनी का निर्देशक या या किसी प्राइवेट कम्पनी द्वारा अपने शेयरधारकों से प्राप्त कोई रकम।"

4. उक्त नियमों के नियम 3 में, उपनियम (2) के खंड (I) में, "(प्राइवेट कम्पनी द्वारा अपने शेयरधारकों से प्रतिगृहीत निक्षेपों से भिन्न)" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जायेगा।

5. उक्त नियमों के नियम 4 में,—

(i) उपनियम (1) में, "जनसाधारण से निक्षेप, जो अपने निवेशकों से निक्षेपों से भिन्न हो, आमंत्रित करना अथवा उनका प्रतिग्रहण करना चाहती है", शब्दों के स्थान पर, "निक्षेप आमंत्रित करता या किसी अन्य व्यक्ति को निक्षेप आमंत्रित करने के लिये अनुज्ञात करता या उसे आमंत्रित करवाना चाहती है", शब्द रखे जायेंगे।

\*य नियम 18 सितम्बर, 1975 से लागू हो गये जबकि इन नियमों का अंग्रेजी संस्करण भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित।

(ii) उपनियम (3) में, "उस वित्तीय वर्ष के जिसमें कि यह जारी किया गया हो, अस्त तक विद्यमान रहेगा", शब्दों के स्थान पर, "उस वित्तीय वर्ष की, जिसमें कि यह जारी किया गया हो, समाप्ति की तारीख से छह मास की समाप्ति पर्यन्त या उस तारीख पर्यन्त, जिसकी कि तुलनपत्र साधारण अधिवेशन में कम्पनी के सामने रखे जायें, या जहां किसी वर्ष का साधारण अधिवेशन न किया गया हो वहां, उस अन्तिम दिन पर्यन्त जिसको कि अधिनियम के उपबन्धों के अनुमरण में अधिवेशन किया जाना था, जो भी पूर्वतर हो, विद्यमान रहेगा,"

6. उक्त नियमों के नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात्:—

"8. निक्षेपों के प्रतिसंदाय की श्राव्य साधारण उपबन्ध—जहां कम्पनी ऐसे निक्षेप की तारीख से छः मास की अवधि के पयवसान के पश्चात् किन्तु उस अवधि की समाप्ति के पूर्व जिसके लिये कम्पनी ने निक्षेप का प्रतिग्रहण किया हो, निक्षेप का प्रतिसंदाय करती है, वहां ऐसे निक्षेप पर कम्पनी द्वारा देय व्याज की दर संविदाकृत दर से दो प्रतिशत घटा दी जायेगी और कम्पनी इस प्रकार घटाई गई दर से किसी उच्चतर दर पर व्याज नहीं देगी।

परन्तु इस नियम में की कोई बात, कम्पनी द्वारा किसी निक्षेप के उस प्रतिसंदाय को लागू नहीं होगी जो उस अवधि की समाप्ति के पूर्व किया जाये जिसके लिये ऐसे निक्षेप का प्रतिग्रहण किया गया हो, यदि—

(I) ऐसा प्रतिसंदाय केवल (क) अर्बकारी अवितीय कम्पनियों (रिजर्व बैंक) निदेश, 1966 या (ख) नियम 3 के उपनियम (3), के उपबन्धों के अनुपालन के प्रयोजनार्थ किया गया हो, या

(II) ऐसा प्रतिसंदाय ऐसी शर्तों और निबन्धनों में, जिनके अधीन निक्षेप कम्पनी द्वारा प्रतिगृहीत किया गया था, विनिर्दिष्ट विकल्प के अनुमरण में किया गया हो।

7. उक्त नियमों के नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात्:—

"10 निक्षेपों की विवरणी रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जायेगी—

(1) प्रत्येक कम्पनी, जिसमें नियम लागू हैं, प्रत्येक वर्ष, 30 जून को या उसके पूर्व, रजिस्ट्रार के पास, इन नियमों से उपवाह्य प्ररूप में और उस वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार जानकारी देते हुये, एक विवरणी दाखिल करेगा।

(2) विवरणी की एक प्रति साथ साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक को दी जावेगी।"

8. उक्त नियमों के नियम 12 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"प्ररूप"

(नियम 10 देखिय)

वित्तीय कम्पनियों से भिन्न अर्बकारी कम्पनियों में 31 मार्च, 19— को यथास्थित निक्षेपों की विवरणी

(1) कम्पनी का नाम —————

(2) पूरा पता —————

(क) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय—

(ख) मुख्य प्रशासनिक कार्यालय—

(3) राज्य, जिसमें कि कम्पनी रजिस्ट्रीकृत है—

(4) प्रास्थिति,\* प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी—

5. कम्पनी की रजिस्ट्रीकृत संख्या—

6. (क) निगमन की तारीख —

(ख) कारबार के प्रारम्भ की तारीख —

7. कम्पनी का वित्तीय वर्ष —

8. मुख्य कारबार, विनिर्माण/व्यापार/कृषि/रोपण/कोई अन्य (उल्लेख कीजिये) :

9. उद्योग का प्रकार: (सूची वस्त्र, चीनी, इंजीनियरी, आदि) :

10. कम्पनी को बैंकर (बैंकों का/के नाम और पता/पते—

\*जो लागू न हो उसे काट दीजिये।

टिप्पण:—विवरणी को पूरा करके, कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास दाखिल किया जाना चाहिये, और उसकी एक प्रति मुख्य अधिकाारी, अर्बकारी कम्पनी विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता को भेजी जानी चाहिये।

भाग—क

बकाया निक्षेप, आदि

31 मार्च, 19—की यथास्थित

निक्षेपों के प्रकार, छूट प्राप्त उधार और प्राप्तियां लेखाओं की रकम (हजार संख्या रूपयों में)

1. नियमों के नियम 3(2)(1) में निर्दिष्ट प्रकार के निक्षेप

(क) पूर्ववर्ती प्रबन्ध अभिकर्ताओं या सचिवों और और कोषपालों द्वारा गारन्टीकृत निक्षेप, जो ऋणों के रूप में प्राप्त किये गये हों।

(ख) अप्रतिभूत डिबेंचर

(ग) ऐसे निक्षेप जिसमें शेयरधारकों से प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के शेयरधारक नहीं प्राप्त अप्रतिभूत ऋण सम्मिलित हैं, किन्तु सनिवेशकों से प्राप्त ऋणों को छोड़कर।

(घ) ऐसे निक्षेप जिनमें निवेशकों द्वारा अपनी वैयक्तिक हैसियत में गारन्टीकृत ऋण सम्मिलित हैं।

1	2	3
(इ) कुल योग (क+ख+ग+घ)		
(II) नियमों के नियम 3(2)(II) में निर्दिष्ट प्रकार के निक्षेप		
(च) नियत निक्षेप		
(छ) कोई अन्य निक्षेप (उन्हें छोड़कर जो नियम 3 में स्पष्टीकरण 1 में अनुबद्ध अपेक्षाओं के अनुसार है।		
(ज) कुल योग (च+छ)		

1	2	3
III. ऐसे छूटप्राप्त उधार निक्षेपों के रूप में नहीं की जाये		
क. नियम 2 के मधीम		
(झ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त राशि जिसके प्रतिसंदाय की गारंटी केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा की गई है।		

[नियम 2(ख) (I)]

(ट) बैंकों और अन्य विविध संस्थाओं से उधार लिये गये :

[नियम 2(ख) (II) और (III)]

(ड) संयुक्त स्टॉक कम्पनियाँ (जिसमें उसी समूह की कम्पनियाँ सम्मिलित हैं) से प्राप्त राशि

[नियम 2 (ख) (iv)]

(ड) कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिभूति निक्षेप  
[नियम 2(ख) (v)]

(ड) क्रय विक्रय या अन्य अभिकर्ताओं से कारबार के प्रयोजनार्थ प्राप्त राशि

[नियम 2(ख) (vi)]

रकम (हजार रुपयों में)

1. गत वर्षों से अग्रणीत रकम
2. वर्ष के दौरान ग्रहण किये गये या नवीकृत निक्षेपों की रकम।

योग

3. वर्ष के दौरान प्रतिसंदत निक्षेपों की रकम

4. वर्ष के अन्त में बकाया निक्षेपों की रकम

5. वर्ष के दौरान ऐसे प्रतिसंदेय निक्षेपों की रकम का योग जिनके लिये दावा नहीं किया गया है।

6. वर्ष के दौरान ऐसे प्रतिसंदेय निक्षेपों की रकम का योग जिनके लिये यद्यपि दावा

किया गया है किन्तु उक्त वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा प्रतिसंदत नहीं की गई है तथा ऐसे अग्रवत्त षेप निक्षेपों की रकम का योग।

(ण) अन्य छूट प्राप्त उधार

[नियम 2(ख) (vii) तथा (viii)]

लेखाओं की संख्या

रकम (हजार रुपयों में)

नियम 3 के अन्तर्गत

(क) निदेशकों से प्राप्त धन राशि

(ख) प्राइवेट कम्पनी की दशा में शेयर धारकों से प्राप्त धनराशि

(ग) प्रतिभूत निक्षेप

प्रतिभूति की प्रकृति और मूल्य, निष्पावित दस्तावेजों की विशिष्टियाँ संक्षेप में पृथक् से उपदिष्ट की जायें।

क और ख का योग

भाग—ख

निक्षेपों की विशिष्टियाँ

31 मार्च 19—को यथास्थिति

निक्षेपों के प्रकार	निक्षेपों की विशिष्टियाँ	लेखाओं की संख्या	रकम (हजार रुपयों में)
---------------------	--------------------------	------------------	-----------------------

1(क) नियम 3(2) (i) के अन्तर्गत निक्षेप (भाग क की मद I के अनुसार)

1. 3 मास से कम के भीतर मांग पर या सूचना पर या अन्यथा प्रतिसंदेय,

2. 6 मास से कम किन्तु 3 मास या उससे अधिक की अवधि के पश्चात् प्रतिसंदेय।

1. नियम 3(2) (ii) के अन्तर्गत निक्षेप (भाग क की मद II के अनुसार)

1. 6 मास से कम भीतर मांग पर या सूचना पर या अन्यथा प्रतिसंदेय।

1. गत वर्षों से अग्रणीत निक्षेपों की रकम।

2. वर्ष के दौरान ग्रहण किये गये या नवीकृत निक्षेपों की रकम

योग

1	2	3
	3. वर्ष के दौरान प्रति-संदत निक्षेपों की रकम	
	4. वर्ष के अन्त में बकाया निक्षेपों की रकम	
	5. वर्ष के दौरान ऐसे प्रतिसंदेय निक्षेपों की रकम का योग जिनके लिये दावा नहीं किया गया है।	
	6. वर्ष के दौरान ऐसे प्रतिसंदेय निक्षेपों की रकम का योग जिनके लिये यद्यपि दावा किया गया है किन्तु उस वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा प्रतिसंदत नहीं की गई है और ऐसे शेष असंदत निक्षेपों की रकम का योग।	

टिप्पणः— (i) ऊपर I और II की मद 4 के सामने दशित रकमें भाग 'क' की कमशः ।

(ii) मदों में दशित रकमों से मिलनी चाहिये ।

(2) यदि निक्षेपों की प्रतिसंदत रकम का योग 5 लाख से अधिक है तो प्रत्येक निक्षेपों का संदाय न किये जाने के कारण और प्रतिसंदाय के लिये की गई कार्रवाइयाँ एक उपबन्ध में दिखाई जाएगी।

भाग—ग

ब्याज की दरें (निक्षेपों, आदि पर दलावी के प्रतिरिक्त)

31 मार्च, 19 को यथास्थिति

निक्षेपों, छूट प्राप्त उधारों और प्राप्तियों के प्रकार	ब्याज की दरें	रकम (हजार रुपयों में)
I. (क) नियम 3(2)(i) के अन्तर्गत निक्षेप (भाग क की मद I के अनुसार)	1. 6 प्रतिशत से कम 2. 6 प्रतिशत या उससे अधिक किन्तु 9 प्रतिशत से कम 3. 9 प्रतिशत या उससे अधिक किन्तु 11 प्रतिशत से कम 4. 11 प्रतिशत या उससे अधिक किन्तु 13 प्रतिशत से कम 5. 13 प्रतिशत या उससे अधिक किन्तु 15 प्रतिशत से कम 6. 15 प्रतिशत या अधिक	
	1 से 6 का योग	

1	2	3
II. नियम 3(2) के अन्तर्गत निक्षेप (भाग क की मद II के अनुसार)	1. 6 प्रतिशत से कम 2. 6 प्रतिशत या अधिक किन्तु 9 प्रतिशत से कम 3. 9 प्रतिशत या अधिक किन्तु 11 प्रतिशत से कम 4. 11 प्रतिशत या अधिक किन्तु 13 प्रतिशत से कम 5. 13 प्रतिशत या अधिक किन्तु 15 प्रतिशत से कम 6. 15 से प्रतिशत या अधिक 1 से 6 तक का योग	
III. छूट प्राप्त ऐसे उधार जिनकी गणना निक्षेपों के रूप में नहीं की जाती (भाग क की मद III के अनुसार)	1. 6 प्रतिशत से कम 2. 6 प्रतिशत या अधिक किन्तु 9 प्रतिशत से कम 3. 9 प्रतिशत या अधिक किन्तु 11 प्रतिशत से कम 4. 11 प्रतिशत या अधिक किन्तु 13 प्रतिशत से कम 5. 13 प्रतिशत या अधिक किन्तु 15 प्रतिशत से कम 6. 15 प्रतिशत या अधिक 1 से 6 तक का योग	

प्रबन्धक का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रेक भाग क, ख और ग के अन्तर्गत निक्षेपों की माझायें और ब्याज की दरें स्थापित की गई हैं और वे ठीक हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि समावस्त पूंजी और मुक्त भार-क्षितियाँ, आदि जिनकी गणना नियम 3 के स्पष्टीकरण 2 में उपदशित पद्धति से की गई हैं निम्नलिखित हैं :—

समावस्त पूंजी ४०  
मुक्त भारक्षितियाँ (विनिविष्ट करें) ४०  
योग

घटायें:	(i) हानि का संचित बकाया ४०
	(ii) आस्थगित राजस्व व्यय का बकाया ४०
	(iii) अन्य मूर्त आस्थितियाँ (विनिविष्ट करें) ४०
	नियमों के नियम 3(2) (i) में निर्दिष्ट प्रकार के निक्षेप (विवरणों के भाग क की मद I के अनुसार) ४०
	(समावस्त पूंजी और मुक्त भार-क्षितियाँ के लिये प्रतिशत) नियमों के नियम 3(2) (ii) में निर्दिष्ट प्रकार के निक्षेप (विवरणों के भाग क की मद II के अनुसार) ४०

समावृत्त पूंजी और मुक्त आर-  
क्षितियों के लिये प्रतिगत)

प्राधिकृत पद-धारी के हस्ताक्षर

नाम-----

तारीख-----

पदाभिधान-----

[सं० 1/21/75-सी० एल० XIV]

ए० चौधरी, संयुक्त सचिव

बर्तीत हजार रुपए मात्र समेकित स्टाम्प शुल्क का संदाय करने की अनुज्ञा  
देती है।

[सं० 45/75/स्टाम्प-फा० सं० 471/83/75-सी० शुल्क-7]

प्रो० पी० मेहरा उप-सचिव

ORDER

STAMPS

(वित्त मंत्रालय)

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर 1975

(आय-कर)

का० आ० 5285—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ की उपधारा (2)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर, पोन-विलैंठकलाथुर को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए तमिलनाडु राज्य में सर्वत्र विख्यात लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती है।

[सं० 1141 फा० सं० 176/91/75-आई० टी० (ए० आई०)]

एम० शास्त्री, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

(INCOME-TAX)

New Delhi, the 29th October, 1975

**S.O. 5285.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies Sri Lakshminarasimhaswamy Temple, Ponvilanthakalathur to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu for the purposes of the said section.

[No. 1141 F. No. 176/91/75-IT(AI)]

M. SHASTRI, Under Secy.

आवेश

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1975

स्टाम्प

का० आ० 5286—केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड इन-वेस्टमेंट कारपोरेशन महाराष्ट्र लिमिटेड, मुम्बई को उक्त निगम द्वारा जारी किए जाने वाले दो करोड़ और बीस लाख रुपए प्रकृत मूल्य के वचन-पत्रों के रूप में बंधपत्रों पर स्टाम्प शुल्क में प्रभाय एक लाख और

**S.O. 5286.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the State Industrial and Investment Corporation of Maharashtra Limited, Bombay to pay consolidated stamp duty of one lakh and thirty-two thousand rupees only, chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of promissory notes of the face value of two crores and twenty lakhs of rupees to be issued by the said Corporation.

[No. 45/75-Stamp-F. No. 471/83/75-Cus-VII]

O. P. MEHRA, Dy. Secy.

(प्राथमिक कार्य विभाग)

पूँजी निर्गम नियंत्रक का कार्यालय

नयी दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1975

का० आ० 5287—पूँजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 29) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने एतद्वारा पूँजी निर्गम नियंत्रण संबंधी सलाहकार समिति की कार्यवाही 22 जून, 1976 तक बढ़ा दी है जिसमें यह तारीख भी शामिल है और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (प्राथमिक कार्य विभाग) की 23 दिसम्बर, 1972 की अधिसूचना संख्या का० आ० 762(ई) में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन किया है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में पैराग्राफ 2 में "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष और छः महीने" शब्द रखे जायेंगे।

[संख्या एक० 16(3)-सी० आई०/72]

जे० पी० मुखर्जी, अतिरिक्त नियंत्रक

(Department of Economic Affairs)

OFFICE OF THE CONTROLLER OF CAPITAL ISSUES

New Delhi, the 2nd December, 1975

**S.O. 5287.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Capital Issues (Control) Act, 1947 (29 of 1947), the Central Government hereby extends the tenure of the Advisory Committee on Capital Issues Control up to and inclusive of the 22nd June, 1976 and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. S.O. 762(E), dated the 23rd December, 1972, namely:—

In the said notification, in paragraph 2, for the words "three years", the words "three years and six months" shall be substituted.

[No. F. 16(3)-CCI/72]

J. P. MUKHERJEE, Additional Controller

## (बैंकिंग विभाग)

नयी दिल्ली, 1 नवम्बर, 1975

का० आ० 5288.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा निम्न सारणी के कालम (1) में उल्लिखित उन अधिकारियों को नियुक्त करती है जो सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के स्तर के समकक्ष अधिकारी होंगे और उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए वे सम्पदा अधिकारी (एस्टेट आफिसर) होंगे। वे अधिकारी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उक्त सारणी के कालम (2) में उल्लिखित सरकारी स्थानों के सम्बन्ध में सम्पदा अधिकारियों (एस्टेट आफिसर) को सौंपे गये कर्तव्यों को पूरा करेंगे।

## सारणी

अधिकारी का पद सरकारी स्थानों की श्रेणियाँ और अधिकार-क्षेत्र की स्थानीय सीमाएँ।

1	2
प्रेसिडेन्ट अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ़ भारत में किसी भी स्थान पर इन्दौर 5, यशवंत निवास मार्ग इन्दौर (म० प्र०)।	स्टेट बैंक ऑफ़ इन्दौर के या इसके द्वारा या इसकी ओर से पट्टे पर लिये गये या अधि-गृहीत स्थान।

[सं० 7(9)-बी० श्री० III/74]

(Department of Banking)

New Delhi, the 1st November, 1975

S. O. 5288.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below, being officers equivalent to the rank of a gazetted officer of Government, to be estate officers for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the estate officers by or under the said Act in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the officer	Categories of Public Premises and local limits of jurisdiction
Premises Officer, State Bank of Indore, 5, Yeshwant Niwas Road, Indore (M.P.)	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of State Bank of Indore at any place in India.

[No. 7 (9)-B.O. III/74]

का० आ० 5289.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा निम्न सारणी के कालम (1) में उल्लिखित उन अधिकारियों को नियुक्त करती है जो सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के स्तर के समकक्ष अधिकारी होंगे और उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए वे सम्पदा अधिकारी (एस्टेट आफिसर) होंगे। वे अधिकारी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उक्त सारणी के कालम (2) में उल्लिखित सरकारी स्थानों के संबंध में सम्पदा अधिकारियों (एस्टेट आफिसर) को सौंपे गये कर्तव्यों को पूरा करेंगे।

## सारणी

अधिकारी का पद	सरकारी स्थानों की श्रेणियाँ और अधिकार-क्षेत्र की स्थानीय सीमाएँ
1	2
प्रेसिडेन्ट अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ़ असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, बीकानेर एण्ड जयपुर (मुख्यालय) सवाई मान सिंह राज मार्ग जयपुर-3।	महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों तथा ञ्छीगढ़ और दिल्ली संघीय राज्य क्षेत्रों में स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर के या इसके द्वारा या इसकी ओर से पट्टे पर लिये गये या अधि-गृहीत स्थान।

[सं० 7(9)-बी० श्री० III/74]

S. O. 5289.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below, being officers equivalent to the rank of a gazetted officer of Government, to be estate officers for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the estate officers by or under the said Act in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the officer	Categories of Public premises and local limits of jurisdiction
Premises Officer, State Bank of Bikaner & Jaipur, Head Office, Sawai Man Singh Highway, Jaipur-3.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of State Bank of Bikaner & Jaipur and Situated in the states of Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Maharashtra, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal and the Union Territories of Chandigarh and Delhi.

[No. 7 (9)-B.O. III/74]

का० आ० 5290.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा निम्न सारणी के कालम (1) में उल्लिखित उन अधिकारियों को नियुक्त करती है जो सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के स्तर के समकक्ष अधिकारी होंगे और उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए वे सम्पदा अधिकारी (एस्टेट आफिसर) होंगे। वे अधिकारी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उक्त सारणी के कालम (2) में उल्लिखित सरकारी स्थानों के संबंध में सम्पदा अधिकारियों (एस्टेट आफिसर) को सौंपे गये कर्तव्यों को पूरा करेंगे।

## सारणी

अधिकारी का पद	सरकारी स्थानों की श्रेणियाँ और अधिकार-क्षेत्र की स्थानीय सीमाएँ
1	2
विधि अधिकारी, स्टेट बैंक आफ पटियाला, मुख्यालय, पटियाला।	भारत में किसी भी स्थान पर स्टेट बैंक आफ पटियाला के या इसके द्वारा या इसकी ओर से पट्टे पर लिये गये या अधि-गृहीत स्थान।
	[सं० 7(9)-बी० प्रो० III/74]

**S.O. 5290.** In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the table below, being officers equivalent to the rank of a gazetted officer of Government, to be estate officers for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the estate officers by or under the said Act in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the officer	Categorise of Public premises and local limits of jurisdiction
Law Officer, State Bank of Patiala, H.O. Patiala.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of State Bank of Patiala at any place in India.

[No. 7(9)—B.O. III/74]

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1975

का० आ० 5291.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा घोषणा करती है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबन्ध 5 नवम्बर, 1976 तक पिण्डले बैंक लिमिटेड, कलकत्ता पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहाँ तक उनका सम्बन्ध बैंक द्वारा कलकत्ता स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड की शोधधारिता से है।

[सं० 15(45)-बी० प्रो० III/75]

New Delhi, the 21st November, 1975

**S.O. 5291.**—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of section 19 of the said Act shall not apply to the Grindlays Bank Ltd., Calcutta till the 5th November

1976 in so far as they relate to its holdings in the shares of Calcutta Steam Navigation Company Ltd.

[No. 15(45)-B. O. III/75]

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1975

का० आ० 5292.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड, द्वारा मोहितशांसगंज इलाहाबाद में धृत सम्पत्ति अर्थात् मकान सं० 116/377 के सम्बन्ध में उक्त बैंक पर 9 नवम्बर, 1976 तक लागू नहीं होंगे।

[सं० 15(44) बी० प्रो० III/75]

में भा० उसगांवकर, अवसर सचिव

New Delhi, the 26th November, 1975

**S.O. 5292.**—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 9 of the said Act shall not apply, till the 9th November 1976 to the Hindustan Commercial Bank Ltd., Kanpur in respect of a property viz. a house No. 116/377 held by it at Mohitshansgan, Allahabad.

[No. 15(44)-B.O. III/75]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1975

का० आ० 5293.—औद्योगिक वित्त नियम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 21 की उपधारा (2) के अनुसरण में, भारतीय औद्योगिक वित्त नियम के निदेशक मंडल की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, नियम द्वारा जनवरी, 1976 में जारी किये जाने वाले तथा जनवरी, 1977 में परिष्कृत होने वाले बाण्डों पर व्याज की दर 9% (नौ प्रतिशत) अधिक निर्धारित करती है।

[सं० 2(48) आई एफ० 1/75]

म० कु० वैकटाचलम, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 25th November, 1975

**S.O. 5293.**—In pursuance of sub-section (2) of Section 21 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948), the Central Government, on the recommendations of the Board of Directors of the Industrial Finance Corporation of India, hereby fixes 9 per cent (Nine per cent) per annum as the rate of interest payable on the bonds to be issued by the said Corporation in January, 1976 and maturing on the 1st January 1977.

[No. 2(48) IF. I/75]

M. K. VENKATACHALAM, Jt. Secy.

## भारतीय रिजर्व बैंक

का० आ० 5294.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में नवम्बर, 1975 के दिनांक 14 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा हस्त विभाग

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1975

देयताएँ	रुपये	रुपये	आस्तियाँ	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	50,69,66,000		सोने का सिक्का और बुलियन :-		
			(क) भारत में रखा हुआ	182,52,56,000	
संचलन में नोट जारी किये गये	6483,86,59,000		(ख) भारत के बाहर रखा हुआ		
कुल नोट		6534,56,25,000	विदेशी प्रतिभूतियाँ	121,73,97,000	
			जोड़		304,26,53,000
			रुपये का सिक्का		9,88,06,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियाँ		6220,41,66,000
			देशी विनियमन बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र		
कुल देयताएँ		6534,56,25,000	कुल आस्तियाँ		6534,56,25,000

दिनांक : 19 नवंबर 1975

के० आर० पुरी, गवर्नर

14 नवम्बर, 1975 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिय विभाग के कार्यकलाप का विवरण

वेयताएँ	रुपये	आस्तियाँ	रुपये
चुक्ता पूंजी	5,00,00,000	मोट	50,69,66,000
भारक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	2,60,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण		छोटा सिक्का	4,50,000
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	334,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल	
राष्ट्रीय कृषि ऋण		(क) देशी	90,63,13,000
(स्थिरीकरण) निधि	140,00,00,000	(ख) विदेशी	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण		(ग) सरकारी खजाना बिल	396,37,35,000
(दीर्घकालीन प्रवर्तन निधि)	390,00,00,000	विदेशों में रखा हुआ ऋण*	785,19,07,000
जमा राशियाँ :—		निवेश**	878,17,55,000
(क) सरकारी		ऋण और भ्रमि :—	
(i) केन्द्रीय सरकार	74,90,73,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	
(ii) राज्य सरकारें	6,91,82,000	(ii) राज्य सरकारों को†	110,14,47,000
(ख) बैंक		ऋण और भ्रमि :—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	592,32,31,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को‡	272,48,50,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	17,84,85,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को @	347,4,87,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,75,41,000	(iii) दूसरों को	12,44,11,000
(iv) अन्य बैंक	81,18,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से	
		ऋण, भ्रमि और निवेश	
		(क) ऋण और भ्रमि :—	
		(i) राज्य सरकारों को	69,59,44,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	12,98,64,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को	
		(iv) कृषि पुनर्निर्माण निगम को	86,70,00,000
(ग) अन्य	1262,51,15,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	10,60,13,000
वेय बिल	158,08,44,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और भ्रमि	
अन्य वेयताएँ	770,77,19,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और भ्रमि	94,34,34,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से	
		ऋण, भ्रमि और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और भ्रमि	333,25,56,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश	
		अन्य आस्तियाँ	353,78,16,000
	रुपये 3904,93,08,000		रुपये 3904,93,08,000

\* नकदी, भावधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

\*\* राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

† राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रवर्त ऋण और भ्रमि शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी प्रोवर-ड्राफ्ट शामिल हैं।

‡ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर भ्रमि दिये गये 72,90,00,000/- रुपये शामिल हैं।

@ राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण)/निधि से प्रवर्त ऋण और भ्रमि शामिल नहीं हैं।

के० आर पुरी, गवर्नर

[सं० फा० 10(1)/75-जी० प्रो० I]

दिनांक: 19 नवम्बर, 1975

ज० व० मीरबन्वासी, अवर सचिव



## RESERVE BANK OF INDIA

New Delhi, the 25th November, 1975.

S.O. 5294.—An account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, for the week ended the 14th day of November 1975  
ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	50,69,66,000		Gold Coin and Bullion:		
Notes in circulation	6483,86,59,000		(a) Held in India	182,52,56,000	
Total notes issued		6534,56,25,000	(b) Held outside India		
			Foreign Securities	121,73,97,000	
			Total		304,26,53,000
			Rupee Coin		9,88,06,000
			Government of India		
			Rupee Securities		6220,41,66,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
Total Liabilities		6534,56,25,000	Total Assets		6534,56,25,000

Dated the 19th day of November 1975.

K.R. PURI, Governor.

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 14th November 1975.

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid up	5,00,00,000	Notes	50,69,66,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Rupee Coin	2,60,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	334,00,00,000	Small Coin	4,50,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	140,00,00,000	Bills Purchased and Discounted:—	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	390,00,00,000	(a) Internal	90,63,13,000
Deposits:—		(b) External	..
(a) Government		(c) Government Treasury Bills	396,37,35,000
(i) Central Government	74,90,73,000	Balances Held Abroad*	785,19,07,000
(ii) State Governments	6,91,82,000	Investments**	878,17,55,000
(b) Banks		Loans and Advances to:—	
(i) Scheduled Commercial Banks	592,32,31,000	(i) Central Government	110,14,47,000
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	17,84,85,000	(ii) State Governments@	
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,75,41,000	Loans and Advances to:—	
(iv) Other Banks	81,18,000	(i) Scheduled Commercial Banks†	272,48,50,000
(c) Others	1262,51,15,000	(ii) State Co-operative Banks‡	347,45,87,000
Bills Payable	158,08,44,000	(iii) Others	12,44,11,000
Other Liabilities	770,77,19,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
RUPEES	3904,93,08,000	(a) Loans and Advances to:—	
		(i) State Governments	69,59,44,000
		(ii) State Co-operative Banks	12,98,64,000
		(iii) Central Land Mortgage Banks	
		(iv) Agricultural Refinance Corporation	86,70,00,000
		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	10,60,13,000
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	94,34,34,000
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	333,25,56,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	
		Other Assets	353,78,16,000
		RUPEES	3904,93,08,000

\* Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

\*\* Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

† Includes Rs. 72, 90,00,000/- advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

‡ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

K.R. PURI, Governor

[No. F 10 (1)/75-BO-I]

Dated the 19th day of November 1975.

C.W. MIRCHANDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1975

का० आ० 5295.—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में नवंबर 1975 के दिनांक 21 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा (हथु विभाग)

देयताएँ	रुपये	रुपये	आस्तियाँ	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	43,87,89,000		सोने का सिक्का और बुलियन :— (क) भारत में रखा हुआ (ख) भारत के बाहर रखा हुआ	182,52,56,000	
संचालन में नोट	6373,49,09,000		विदेशी प्रतिभूतियाँ	121,73,97,000	
			जोड़		304,26,53,000
जारी किये गये कुल नोट		6417,36,98,000	रुपये का सिक्का भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियाँ देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र		12,70,03,000 6100,40,42,000
कुल देयताएँ		6417,36,98,000	कुल आस्तियाँ		6417,36,98,000

दिनांक : 26 नवंबर 1975

भार० के० हजारी, उप गवर्नर

21 नवंबर 1975 को भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएँ	रुपये	आस्तियाँ	रुपये
चुकता पूंजी	5,00,00,000	नोट	43,87,89,000
भारक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	4,08,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	334,00,00,000	छोटा सिक्का	4,87,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	140,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल	..
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	390,00,00,000	(क) देशी	99,75,14,000
जमा राशियाँ :—		(ख) विदेशी	..
(क) सरकारी		(ग) सरकारी खजाना बिल	374,81,43,000
(i) केन्द्रीय सरकार	63,95,03,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	792,78,85,000
(ii) राज्य सरकारें	10,72,33,000	निवेश**	979,25,33,000
(ख) बैंक		ऋण और अधिम :—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	525,68,85,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	..
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	19,17,41,000	(ii) राज्य सरकारों को (1)	118,60,89,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक		ऋण और अधिम :—	
(iv) अन्य बैंक	1,63,40,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को†	151,37,00,000
	54,74,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को‡	344,17,11,000
		(iii) दूसरों को	11,67,51,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से	
		ऋण, अधिम और निवेश	
		(क) ऋण और अधिम :—	
		(i) राज्य सरकारों को	69,59,44,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	12,88,54,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को	..
		(iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को	86,70,00,000
		(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	10,60,13,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अधिम	
देय बिल	160,00,48,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अधिम	94,42,82,000
अन्य देयताएँ	792,47,61,000	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से	
		ऋण, अधिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अधिम	333,25,56,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बाडों/डिबेंचरों में निवेश	..
		अन्य आस्तियाँ	351,73,75,000
रुपये	3875,60,34,000	रुपये	3875,60,34,000

\*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

\*\*राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अधिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

†भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अधिम दिये गये 43,77,50,000 रुपये शामिल हैं।

‡राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अधिम शामिल नहीं हैं।

दिनांक : 26 नवम्बर, 1975

भार० के० हजारी, उप गवर्नर  
[सं० 10(1)/75-बी०प्रो० I]

ब० व० मीरजन्तानी, अवब सचिव

New Delhi, the 2nd December, 1975

An account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 for the week ended the 21st day of November, 1975  
ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	43,87,89,000		Gold Coin and Bullion:—		
Notes in circulation	6373,49,09,000		(a) Held in India	182,52,56,000	
Total notes issued		6417,36,98,000	(b) Held outside India		
			Foreign Securities	121,73,97,000	
			Total		304,26,53,000
			Rupee Coin		12,70,03,000
			Government of India		
			Rupee Securities		6100,40,42,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper		
Total Liabilities		6417,36,98,000	Total Assets		6417,36,98,000

Dated the 26th day of November 1975.

R.K. HAZARI  
Dy. Governor

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 21st November 1975.

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	43,87,89,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Rupee Coin	4,08,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	334,00,00,000	Small Coin	4,87,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	140,00,00,000	Bills Purchased and Discounted:—	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	390,00,00,000	(a) Internal	99,75,14,000
Deposits:—		(b) External	374,81,43,000
(a) Government		(c) Government Treasury Bills	792,78,85,000
(i) Central Government	63,95,03,000	Balances Held Abroad*	979,25,33,000
(ii) State Governments	10,72,33,000	Investments**	
(b) Banks		Loans and Advances to:—	
(i) Scheduled Commercial Banks	525,68,85,000	(i) Central Government	
(ii) Schedule I State Co-operative Banks	19,17,41,000	(ii) State Governments@	118,60,89,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,63,40,000	Loans and Advances to:—	
(iv) Other Banks	54,74,000	(i) Scheduled Commercial Banks†	151,37,00,000
(c) Others	1282,40,49,000	(ii) State Co-operative Banks‡	344,17,11,000
Bills Payable	160,00,48,000	(iii) Others	11,67,51,000
Other Liabilities	792,47,61,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
RUPEES	3875,60,34,000	(a) Loans and Advances to:—	
		(i) State Governments	69,59,44,000
		(ii) State Co-operative Banks	12,88,54,000
		(iii) Central Land Mortgage Banks	
		(iv) Agricultural Refinance Corporation	86,70,00,000
		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	10,60,13,000
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	94,42,82,000
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	333,25,56,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	
		Other Assets	351,73,75,000
		RUPEES	3875,60,34,00

\* Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

\*\* Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

† Includes Rs. 43,77,50,000/- advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17 (4) (c) of the Reserve Bank of India Act.

‡ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 26th day of November 1975.

R.K. HAZARI  
Dy. Governor

[No. F. 10 (1)/75—BOI]

C. W. MIRCHANDANI, Under Secy.

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 28th October, 1975

**S.O. 5296.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Contributory Provident Fund (India) Fourth Amendment Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, (a) in rule 8 for the second proviso to sub-rule (4), the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided further that if a subscriber is on leave without pay or leave on half pay or half average pay for part of a calendar month and he has elected not to subscribe during such leave, the amount of subscription payable shall be proportionate to the number of days spent on duty including leave if any other then those referred to above."

(b) in rule 14, in sub-rule (2) in clause (a) :—(i) after the words "or is on leave", the words "for ten days or more in a calendar month" shall be inserted.

(ii) the proviso shall be omitted.

[No. 13(4)-E.V.(B)/75-(GPF)]

**S.O. 5297.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services) Fifth Amendment Rules, 1975 ;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 :—

(a) in rule 8, for second proviso to sub-rule (4), the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided further that if a subscriber is on leave without Pay or leave on half Pay or half average pay for a part of a calendar month and he has elected not to subscribe during such leave, the amount of subscription payable shall be proportionate to the number of days spent on duty including leave, if any, other than those referred to above."

(b) in rule 13, in sub-rule (2) after the words "or is on leave", the words "for ten days or more in a calendar month" shall be inserted.

[No. 13(4)-E.V.(B)/75-G.P.F.]

S. S. MALHOTRA, Under Secy.

(व्यय विभाग)

आवेश

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1975

क्र० आ० 5298:—केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 9 के उपनियम (2) और नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जी एतद्वारा निदेश देते हैं कि इस आदेश की

अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 2 में पदों के संबंध में उक्त अनुसूची के कालम 2 और 3 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कालम 4 में विनिर्दिष्ट दण्ड के संबंध में क्रमशः नियुक्ति प्राधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे।

अनुसूची

पद का विवरण नियुक्ति प्राधिकारी दण्ड लगाने का सक्षम प्राधिकारी और दण्ड जिन्हें लगाया जा सकता है [केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 11 में मर संख्या के संदर्भ में]

प्राधिकारी		दण्ड	
1	2	3	4
वित्त मंत्रालय संयुक्त सचिव, व्यय (असैनिक) विभाग (सरकारी उद्यम व्यूरो को छोड़कर) सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी II में शामिल सभी पद।	संयुक्त सचिव, प्रशासन, वित्त प्रशासन, व्यय मंत्रालय, व्यय (असैनिक) विभाग (असैनिक) विभाग	संयुक्त सचिव, प्रशासन, वित्त प्रशासन, व्यय मंत्रालय, व्यय (असैनिक) विभाग	सभी

[सं० सी० 11011/1/75-सं०-1(ख)]

र० ल० सूद, अवर सचिव

## ORDER

New Delhi, the 29th November, 1975

**S.O. 5298.**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9 and clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 the President hereby directs that in respect of the posts in the General Central Service, Class II, specified in column 1 of the Schedule to this order, the authorities specified in columns 2 & 3 of the said Schedule shall respectively be the Appointing Authority and the Disciplinary Authority in regard to the penalties specified in column 4 thereof.

## SCHEDULE

Description of Post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item numbers in Rule 11 of the Central Civil Services) (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.	Authority	Penalties
1	2	3	4	5

Ministry of Finance  
(Department of Expenditure)  
(Civil) (excluding the Bureau of Public Enterprises).

All posts included in the General Central Service Class II.	Joint Secretary in-charge of Administration, Ministry of Finance, (Department of Expenditure) (Civil).	Joint Secretary in-charge of Administration, Ministry of Finance, (Department of Expenditure) (Civil).	All
---	--	--	-----

[No. C. 11011/1/75—E.I. (B)]  
R.L. SUD, Under Secy.

### केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1975

प्राय-कर

क्र० आ० 5299.—प्राय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड समय समय पर यथा संशोधित, अपनी अधिसूचना सं० 729 (फा० सं० 261/4/74-आई०टी०जे०) तारीख 30-9-74 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

उक्त अनुसूची में

(क) 'थ' रेंज, कलकत्ता के सामने, निम्नलिखित रखा जाएगा:—

- (1) हुण्डी सिकिल, कलकत्ता।
- (2) विशेष सिकिल-1, हुण्डी सिकिल, कलकत्ता।
- (3) विशेष सिकिल-2, हुण्डी सिकिल, कलकत्ता।
- (4) जिला-8, कलकत्ता।

(ख) 'ड' रेंज, कलकत्ता के सामने, निम्नलिखित रखा जाएगा:—

- (1) जिला 3 क, कलकत्ता।
- (2) जिला 5 क, कलकत्ता।
- (3) प्रतिदाय सिकिल, कलकत्ता।
- (4) बीमा अभिकता सिकिल, कलकत्ता।
- (5) न्यास सिकिल, कलकत्ता।
- (6) चार्टर्ड एकाउण्टेंट सिकिल, कलकत्ता।

यह अधिसूचना 1-9-75 से प्रभावी होगी।

[सं० 1023 फा० सं० 261/8/75-आई० टी० जे०]

### CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

#### INCOME-TAX

New Delhi, the 8th August, 1975

S.O. 5299.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment to the Schedule appended to its Notification No. 729 (F. No. 261/4/74-ITJ) dated 30-9-1974 as amended from time to time.

#### IN THE SAID SCHEDULE

(a) Against 'Q' Range, Calcutta, following shall be substituted:—

- (1) Hundi Circle, Calcutta.
- (2) Special Circle-I, Hundi Circle, Calcutta.
- (3) Special Circle-II, Hundi Circle, Calcutta.
- (4) District-VIII, Calcutta.

(b) Against 'N' Range, Calcutta, the following shall be substituted:—

- (1) District IIIA, Calcutta.
- (2) District VA, Calcutta.
- (3) Refund Circle, Calcutta.
- (4) Insurance Agents Circle, Calcutta.
- (5) Trust Circle, Calcutta.
- (6) Chartered Accountants Circle, Calcutta.

This Notification shall take effect from 1-9-1975.

#### EXPLANATORY NOTE :

The amendment has become necessary consequent on creation of Separate Professional Circle.

The above note does not form a part of Notification but is intended to be merely clarificatory.

[No. 1023/F. No. 261/8/75-ITJ]

प्राय-कर

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1975

क्र० आ० 5300.—अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, समय समय पर यथा संशोधित, अपनी अधिसूचना सं० 729 तारीख 30-9-74 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है।

उक्त अनुसूची में

I. क्रम सं० 16 के सामने, त-रेंज, कलकत्ता के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:—

- (1) जिला IV (2), कलकत्ता (क, प्रतिरिक्त क, ख, ग और झ बाईं)।

II. क्रम सं० 23 के सामने, ब-रेंज, कलकत्ता के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:—

- (1) क्रम० जिला II से, कलकत्ता (क से ख तक और प्रतिरिक्त ख बाईं से शिफ़)।

III. क्रम सं० 24 के सामने, भ-रेंज, कलकत्ता के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:—

- (1) जिला IV (3), कलकत्ता (क से ख तक बाईं)।
- (2) जिला IV (2), कलकत्ता (प्रतिरिक्त छ बाईं और विशेष सिकिल, VIII)।

IV. क्रम सं० 33 के सामने, क छ-रेंज, कलकत्ता के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:—

- (1) जिला I (2), कलकत्ता (क से छ तक बाईं)।

V. क्रम सं० 39 के सामने, क ड-रेंज, कलकत्ता के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:—

- (1) जिला VI, कलकत्ता (ड से ड तक बाईं)।

VI. क्रम सं० 44 के सामने, क व-रेंज, कलकत्ता के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:—

- (1) जिला IV (2), कलकत्ता (घ और झ बाईं)।

VII क्रम सं० 43 पश्चात् बर्दवान रेंज के स्थान पर निम्न-लिखित जोड़ा जाएगा :—

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2	स्तम्भ 3
क्रम सं० 55	क-ब रेंज, कलकत्ता	(1) सिनेमा सर्किल, कलकत्ता
क्रम सं० 56	क-भ रेंज, कलकत्ता	(1) जिला I (2), कलकत्ता (क से ग तक के वार्डों से भिन्न) ।
क्रम सं० 57	क-ब रेंज, कलकत्ता	(1) जिला VI, कलकत्ता (क से ड तक के वार्डों से भिन्न) ।
क्रम सं० 58	क-य रेंज, कलकत्ता	(1) जिला IV (2), कलकत्ता (क से ड भा, अतिरिक्त क अतिरिक्त छ और विशेष सर्किल VIII से भिन्न)

यह अधिसूचना 16-3-75 से प्रभावी होगी।

[सं० 1043 (फा० सं० 261/8/75-आई०टी०जे०)]

### INCOME-TAX

New Delhi, the 16th August, 1975

**S.O. 5300.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (4 of 1961), and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the (Schedule appended to its Notification No. 729 dated 30-9-1974 as amended from time to time viz.

### IN THE SAID SCHEDULE

I. Against Sl. 16 for P-Range, Calcutta the following shall be substituted—

(1) Distt. IV(2), Calcutta (A), Addl. A, B, C & I Wards).

II. Against Sl. 23 for W-Range, Calcutta the following shall be substituted.

(1) Comp. Distt. II, Calcutta (other than A to F and Addl. B. Wards).

III. Against Sl. 24 for X-Range, Calcutta the following shall be substituted.

(1) Dist. IV(3), Calcutta (A to F Wards).

(2) Dist. IV(2), Calcutta Addl. G-Ward and Special Circle VIII)

IV. Against Sl. 33 for AG-Range, Calcutta the following shall be substituted.

(1) Dist. (2), Calcutta (A to G-Wards).

V. Against Sl. 39 for Am-Range, Calcutta the following shall be substituted.

(1) Dist. VI Calcutta (K to N-Wards).

VI. Against Sl. 44 for AR-Range, Calcutta the following shall be substituted.

(1) Dist. IV(2), Calcutta (D & E Wards).

VII. After Sl. 54 for Burdwan Range add the following:—

Col. 1	Col. 2	Col. 3
Sl.55	AW Range, Calcutta.	(1) Cinema Circle, Calcutta.
Sl.56	AX Range, Calcutta	(1) Dist. 1(2), Calcutta. (other than A to G wards)
Sl.57	AY Range, Calcutta.	(1) Dist. VI, Calcutta (other than A to N Wards.)
Sl.58	AZ Range, Calcutta.	(1) Dist IV 1(2), Calcutta. (other than A to E, I Addl A, Addl.G and Spl.Circle. VIII).

This notification shall take effect from 16-8-1975.

### EXPLANATORY NOTE

The amendment has become necessary consequent on re-distribution of the workload in certain Appellate Ranges in Calcutta.

The above note does not form a part of notification but if, intended to be merely clarificatory).

[No. 1043 (F. No. 261/8/75-ITJ)]

P. MISRA, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

प्राय-कर

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1975

फा० आ० 5301.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अधिसूचना सं० 979 (फा० सं० 261/8/75-आई० टी० जे०) तारीख 23-7-1975 में,—

“यह अधिसूचना 25-7-75 से प्रभावी होगी” पंक्ति में “25-7-1975” के स्थान पर “1-9-1975” पढ़ें।

[सं० 1067 (फा० सं० 261/8/75-आई०टी०जे०)] ।

### CORRIGENDUM

### INCOME-TAX

New Delhi, the 1st September, 1975

**S.O. 5301.**—In the notification of the Central Board of Direct Taxes No. 979 (F. No. 261/8/75-ITJ3 dated 23-7-1975.

In line “This Notification shall take effect from 25-7-75” for “25-7-1975” read “1-9-1975”.

[No. 1067 (F. No. 261/8/75-ITJ)]

फा० आ० 5302.—प्राय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त ससर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड समय-समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं० 729 तारीख 30-9-74 से उपाखण्ड अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है।

### अनुसूची में

(1) क्रम सं० 22 के सामने, मद 3 में क-रेंज, कलकत्ता के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :—

1. जिला III (2) कलकत्ता, (क से ग तक वार्ड)
2. विदेशी कम्पनी सर्किल, कलकत्ता।

(2) क्रम सं० 13 के सामने, स्तम्भ 3 में ड-रेंज, कलकत्ता के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :—

1. जिला II (2), कलकत्ता (क से ख तक वार्ड)।
2. विशेष अन्वेषण सर्किल-1, कलकत्ता।

(3) क्रम सं० 43 के सामने, स्तम्भ 3 में क थ-रेंज, कलकत्ता के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :—

1. विशेष सर्वेक्षण सर्किल-IX, कलकत्ता।
2. मिथनापुर।
3. विशेष अन्वेषण सर्किल-II, कलकत्ता।

(4) कम सं० 52 के सामने, स्तम्भ 3 में, जलपाईगुड़ी, ख-रेंज के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :—

1. आय-कर सफिल, सिलीगुड़ी;
2. आय-कर सफिल, दार्जिलिंग;
3. विशेष सफिल, सिलीगुड़ी।
4. पश्चिम दिनाजपुर और मालदा।

यह अधिसूचना 1-9-1975 से प्रभावी होगी।

[सं० 1068 (फा० सं० 261/8/75-आई० टी० जे०)]

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st October, 1975

S.O. 5303.—In the notification of the Central Board of Direct Taxes No. 1068 (F. No. 261/8/75-ITJ) dated 1-9-1975.

In line "This notification shall take effect from 1-9-1975".

for "1-9-1975" read "1-10-1975".

[No. 1110 (F. No. 261/8/75-ITJ)]

P. MISRA, Under Secy.

S.O. 5302.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the Schedule appended to its Notification No. 729 dated 30-9-74 as amended from time to time.

## IN THE SCHEDULE.

- (1) Against Sl. 22 for V-Range, Calcutta in column 3, the following shall be substituted:—
  1. District III(2), Calcutta (A to C Wards);
  2. Foreign Companies Circle, Calcutta.
- (2) Against Sl. 13 for M-Range, Calcutta in column 3, the following shall be substituted:—
  1. District II(2), Calcutta (A to D Wards).
  2. Special Investigation Circle-1, Calcutta.
- (3) Against Sl. 43 for AQ-Range, Calcutta in column 3 the following shall be substituted:—
  1. Special Survey Circle-IX, Calcutta.
  2. Midnapore;
  3. Special Investigation Circle-II, Calcutta.
- (4) Against Sl. 52 for Jalpaiguri B-Range in column 3 the following shall be substituted:—
  1. Income-tax Circle, Shilliguri;
  2. Income-tax Circle, Darjeeling.
  3. Special Circle, Siliguri.
  4. West Dinajpur & Maidah.

This notification shall take effect from 1-9-1975.

## EXPLANATORY NOTE :

The amendment has become necessary consequent on creation of a Foreign Companies Circle and 2 special Investigation Circles in West Bengal.

(The above note does not form a part of notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 1068 (F. No. 261/8/75-ITJ)]

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 1975

का० प्रा० 5303.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं० 1068 (फा० सं० 261/8/75-आई० टी० जे०), तारीख 1-9-75 में,

"यह अधिसूचना 1-9-75 से प्रभावी होगी" पंक्ति में,  
"1-9-75" के स्थान पर "1-10-1975" पढ़ें।

[सं० 1110 (फा० सं० 261/8/75-आई० टी० जे०)]

पी० मिश्र, अवसर सचिव

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1975

का० प्रा० 5304.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बोर्ड की अधिसूचना सं० 586 (फा० सं० 261/8/74-आई० टी० जे०) तारीख 30-3-74 की आंशिक रूप से उपान्तरित करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश करता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आय-कर आयुक्त (अपील), उसके स्तम्भ 2 में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आय-कर सफिलों, वाडों और जिलों में आय-कर या अधिपर के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों और आय की बाबत अपने कृत्यों का पालन करेंगे :—

## अनुसूची

रेंज	आय-कर सफिल,	वाडें और जिला
सहायक आय-कर आयुक्त (अपील), क-रेंज नागपुर	1. आय-कर अधिकारी, ख-वाडें,	नागपुर
	2. " ध-वाडें,	नागपुर
	3. " ड-वाडें,	नागपुर
	4. " च-वाडें,	नागपुर
	5. " छ-वाडें,	नागपुर
	6. " झ-वाडें,	नागपुर
	7. " ञ-वाडें,	नागपुर
	8. " ट-वाडें,	नागपुर
	9. " ठ-वाडें,	नागपुर
	10. " त-वाडें,	नागपुर
	11. " नगर सफिल, नागपुर	
	12. " केन्द्रीय सफिल-1,	नागपुर
	13. " केन्द्रीय सफिल-2,	नागपुर
	14. " केन्द्रीय सफिल-3,	नागपुर
	15. " केन्द्रीय सफिल-4,	नागपुर
	16. " क-वाडें,	गोंदिया
	17. " ख-वाडें,	गोंदिया
	18. " क-वाडें,	अमरावती
	19. " ख-वाडें,	अमरावती
	20. " ग-वाडें,	अमरावती

1	2
भायकर-अधिकारी	21. " ब-वार्ड, अमरावती
	22. " यवतमाल
	23. " क-वार्ड, यवतमाल
	24. " ख-वार्ड, यवतमाल
सहायक भाय-कर आयुक्त (अपील), ख-रेंज नागपुर	1. " क-वार्ड, नागपुर
	2. " ग-वार्ड, नागपुर
	3. " ज-वार्ड, नागपुर
	4. " ड-वार्ड, नागपुर
	5. " ढ-वार्ड, नागपुर
	6. " न्यास सफिल, नागपुर
	7. " प्रथम आई० टी० ओ०
	8. " वेतन सफिल, नागपुर
	9. " द्वितीय आई० टी०
	10. " ओ० वेतन सफिल, नागपुर
	11. " सर्वेक्षण सफिल, नागपुर
	12. " भाय-कर अधिकारी, वर्धा
	13. " क-वार्ड, चन्द्रपुर
	14. " ख-वार्ड, चन्द्रपुर
	15. " ग-वार्ड, चन्द्रपुर
	16. " ङ-वार्ड, चन्द्रपुर
सहायक भाय-कर आयुक्त (अपील), श्रीरंगाबाद रेंज, श्रीरंगाबाद	1. " क-वार्ड, श्रीरंगाबाद
	2. " ख-वार्ड, श्रीरंगाबाद
	3. " ग-वार्ड, श्रीरंगाबाद
	4. " ङ-वार्ड, श्रीरंगाबाद
	5. " क-वार्ड, नांदेड
	6. " ख-वार्ड, नांदेड
	7. " ग-वार्ड, नांदेड
	8. " क-वार्ड, जालना
	9. " ख-वार्ड, जालना
	10. " न्यास सफिल, जालना
	11. " सादूर
	12. " क-वार्ड, सादूर
	13. " ख-वार्ड, सादूर
	14. " परभनी
	15. " भीर
सहायक भाय-कर आयुक्त (अपील), अकोला रेंज, अकोला	1. " क-वार्ड, अकोला
	2. " ख-वार्ड, अकोला
	3. " ग-वार्ड, अकोला
	4. " ङ-वार्ड, अकोला
	5. " क-वार्ड, अकोला
	6. " केन्द्रीय सफिल, अकोला
	7. " ए० सी० ई० डी०, अकोला
	8. " सर्वेक्षण सफिल, अकोला
	9. " विशेष अन्वेषण सफिल, अकोला
	10. " खामगांव

जहां कोई भाय-कर सफिल, वार्ड या जिला या उसका भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज को अन्तरित कर दिया जाता है, वहां उस भाय-कर सफिल, वार्ड या जिला या उसके भाग में किए गए निष्पत्तियों के फलस्वरूप होने वाली और उस रेंज के, जिसके वह भाय-कर सफिल, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तरित किया गया है, सहायक भाय-कर आयुक्त (अपील) के समक्ष इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पूर्व लिखित अपीलें, उस तारीख से, जिसको यह अधिसूचना प्रभावी हो, उस रेंज के, जिसको उक्त सफिल, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तरित किया गया है, सहायक भाय-कर आयुक्त (अपील) को अन्तरित की जाएगी और उसके द्वारा उन पर कार्यवाही की जाएगी।

यह अधिसूचना 18-8-1975 से प्रभावी होगी।

[सं० 1045 (फा० सं० 261/16/75-आई. टी. जे.)]

New Delhi, the 16th August, 1975

**S.O.5304**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income tax Act 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in that behalf and in partial modification of Board's notification No. 586 (F. No. 261/8/74-ITJ) dated 30-3-74, the Central Board of Direct Taxes, hereby directs that the Appellate Assistant Commissioner of Income tax of the Ranges specified in Column 1 of the Schedule below shall perform their functions in respect of all the persons and income assessed to Income tax and super tax in the Income tax Circle, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column 2 thereof:

#### SCHEDULE

Range	Income tax Circle, Ward & District
Appellate Assistant	1. Income tax B-Ward, Nagpur. Officer,
Commissioner of Income tax,	2. Do. D-Ward, Nagpur.
A-Range, Nagpur.	3. Do. E-Ward, Nagpur.
	4. Do. F-Ward, Nagpur.
	5. Do. G-Ward, Nagpur.
	6. Do. I-Ward, Nagpur.
	7. Do. J-Ward, Nagpur.
	8. Do. K-Ward, Nagpur.
	9. Do. L-Ward, Nagpur.
	10. Do. P-Ward, Nagpur.
	11. Do. City Circle, Nagpur.
	12. Do. Central Circle-I, Nagpur.
	13. Do. Central Circle-II, Nagpur.
	14. Do. Central Circle-III, Nagpur.
	15. Do. Central Circle-IV, Nagpur.
	16. Do. A-Ward, Gondia.
	17. Do. B-Ward, Gondia.
	18. Do. A-Ward, Amravati.
	19. Do. B-Ward, Amravati.
	20. Do. C-Ward, Amravati.
	21. Do. D-Ward, Amravati.
	22. Do. Yeotmal.
	23. Do. A-Ward, Yeotmal.
	24. Do. B-Ward, Yeotmal.



Appellate Assistant Commissioner of Income Tax, B-Range, Nagpur,	1.	Do.	A-Ward, Nagpur.
	2.	Do.	C-Ward, Nagpur.
	3.	Do.	H-Ward, Nagpur.
	4.	Do.	M-Ward, Nagpur.
	5.	Do.	N-Ward, Nagpur.
	6.	Do.	Trust Circle, Nagpur.
	7.	Do.	1st I.T.O. Salary Circle, Nagpur.
	8.	Do.	2nd I.T.O. Salary Circle, Nagpur.
	9.	Do.	Survey Circle, Nagpur.
	10.	Do.	Incometax Officer, Wardha.
	11.	Do.	A-Ward, Chandrapur.
	12.	Do.	B-Ward, Chandrapur.
	13.	Do.	C-Ward, Chandrapur.
	14.	Do.	D-Ward, Chandrapur.
Appellate Assistant Commissioner of Income-tax Aurangabad Range, Aurangabad.	1.	Do.	A-Ward, Aurangabad.
	2.	Do.	B-Ward, Aurangabad.
	3.	Do.	C-Ward, Aurangabad.
	4.	Do.	D-Ward, Aurangabad.
	5.	Do.	E-Ward, Aurangabad.
	6.	Do.	A-Ward, Nandad.
	7.	Do.	B-Ward, Nandad.
	8.	Do.	C-Ward, Nandad.
	9.	Do.	A-Ward, Jalana.
	10.	Do.	B-Ward, Jalana.
	11.	Do.	Trust Circle, Jalna.
	12.	Do.	Latur.
	13.	Do.	A-Ward, Lature.
	14.	Do.	B-Ward, Latur.
	15.	Do.	Parbhani.
	16.	Do.	Bhir.
Appellate Assistant Commissioner of Income-Tax, Akola Range Akola.	1.	Do.	A-Ward, Akola.
	2.	Do.	B-Ward, Akola.
	3.	Do.	C-Ward, Akola.
	4.	Do.	D-Ward, Akola.
	5.	Do.	E-Ward, Akola.
	6.	Do.	Central Circle, Akola.
	7.	Do.	A-C- E.D. Akola.
	8.	Do.	Survey Circle, Akola.
	9.	Do.	Spl. Investigation Circle, Akola.
	10.	Do.	Khamgaon.

Where an Incometax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this notification from one range to another range, appeal arising out pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom that Incometax Circle, Ward of district or part thereof is transferred shall from the date of this notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Asstt. Commissioner of Incometax of the Range to whom the said circle, ward or district, part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 18-8-75.

#### EXPLANATORY NOTE:

The amendment has become necessary consequent upon redistribution of jurisdiction of Appellate Assistant Commissioners of Income-tax.

(The above note does not form a part of notification but is intended to be merely clarificatory)

[No. 1045 (F.No. 261/16/75-ITJ)]

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1975

का. ग्रा. 5305. — आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 122 की उप-धारा (1) द्वारा प्रवक्त शक्तियों और इस निमित्त समर्थ बनाने वाली 114 GI/75—3

अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपनी अधिसूचना सं. 746 (फा. सं. 261/19/74-आई. टी. जे.) तारीख 10-10-74, सं. 781 (फा. सं. 261/19/74-आई. टी. जे.) तारीख 25-11-74 सं. 813 (फा. सं. 261/19/74-आई. टी. जे.) तारीख 9-1-75 से उपाखण्ड अनुसूची और तारीख 20-2-75 के शुद्धिपत्र में निम्नलिखित संशोधन करता है।

उक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित परिवर्तन किया जाएगा :—

- | क्रम | रेंज                                     | जोड़ा गया आय-कर सर्किल/वार्ड सं.                                       |
|------|--|--|
| 10.  | सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) आर. आर. राजकोट | प्रविष्टि सं. 3 "जूनागढ़ सर्किल" का विलोप किया जाएगा।                  |
| 12.  | सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) जे. आर. जामनगर | प्रविष्टि सं. 3 "पोरबन्दर सर्किल" के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :— |
|      |  | 4. "जूनागढ़ सर्किल।"   |

जहां कोई आय-कर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज को अन्तर्गत कर दिया जाता है, वहां उस आय-कर सर्किल वार्ड या जिला या उसके भाग में किए गए निर्धारणों के फलस्वरूप होने वाली और उस रेंज के, जिससे वह आय-कर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तर्गत किया गया है, सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) के समक्ष इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पूर्व लिखित अपीलें, उस तारीख से, जिसको यह अधिसूचना प्रभावी हो, उस रेंज के, जिसको उक्त सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तर्गत किया गया है, सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) को अन्तर्गत की जाएगी और उसके द्वारा उन पर कार्यवाही की जाएगी।

यह अधिसूचना 8 सितम्बर, 1975 से लागू होगी।

[सं. 1071 (फा. सं. 261/15/75-आई. टी. जे.)]  
एस. रामस्वामी, अवर सचिव

New Delhi, the 8th September, 1975

S.O. 5305.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 and of all others powers enabling it in that behalf of the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the schedule appended to its Notification No. 746 (F. No. 261/19/74-ITJ) dated 10-10-74, No. 781 (F. No. 261/19/74-ITJ) dated 25-11-74, No. 813 (F. No. 261/19/74-ITJ) dated 9-1-1975, No. 976 (F. No. 261/15/75-ITJ) dated 19-7-75 and corrigendum dated 20-2-75.

In the said schedule the following alteration shall be made.

- |     |                      |  |
|-----|----------------------|--|
| 10. | A.A.C.R.R. Rajkot.   | Entry No. 3. "Junagadh Circle" may be deleted.           |
| 12. | A.A.C.J.R. Jamnagar. | After "Entry No. 3" Circle the following shall be added, |
|     |                      | 4. "Junagadh Circle."                                    |

Where an I.T. Circle, Ward and District or part thereof stands transferred by this notification from one range to another Range, appeals arising out of assessments made in that I.T. Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Asstt. Commissioner of Income-tax from when that Income Tax Circle, Ward on District or part thereof is transferred shall, from the date this notification, take effect be transferred to, and dealt with by the Appellate Asstt. Commissioner of Income-tax of the range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from the 8th September, 1975.

#### EXPLANATORY NOTE :

(This amendment has become necessary consequent on redistribution of the word load of A.A.Cs. in Gujarat V Charge.

The above note does not form a part of notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 1074 (F. No. 261/15/75-ITJ)]

क्रा० प्रा० 5306.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं० 841 (फा० सं० 261/12/75-प्राई० टी० जे०) तारीख 20-2-1975 को उपात्तरित करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निवेश करता है कि उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं० 4 में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी :—

अनुसूची		
क्रम सं०	रेंज	आय-कर सर्किल, वार्ड और जिले
1	2	3
4. विशेष रेंज, कानपुर	(i) विशेष रेंज कानपुर	
	(ii) कम्पनी सर्किल, कानपुर	
	(iii) फतेहगढ़ सर्किल	
	(iv) बांदा सर्किल	
	(v) केन्द्रीय सर्किल 3, 4 और 5 कानपुर	

जहाँ कोई आय-कर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज को अन्तर्गत कर दिया जाता है वहाँ उस आय-कर सर्किल, वार्ड या जिला या उसके भाग में किए गए निर्धारणों के फलस्वरूप होने वाली और उस रेंज के, जिससे वह आय-कर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तर्गत किया गया है, सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) के समक्ष इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पूर्व लम्बित अपीलें, उस तारीख से, जिसको यह अधिसूचना प्रभावी हो, उस रेंज के, जिसको उक्त सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तर्गत किया गया है, सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) को अन्तर्गत की जाएँगी और उसके द्वारा उन पर कार्यवाही की जाएगी ।

यह अधिसूचना 1-10-1975 से प्रभावी होगी ।

[सं० 1075 (फा० सं० 261/1/75-प्राई० टी० जे०)]

S.O. 5306—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in modification of notification No. 841 (F.No.261/12/75-ITJ) dated 20-2-1975 the Central Board of Direct Taxes hereby direct that the entries at Sl. No. 4 in the Schedule to the said Notification shall be substituted by the following entries :—

#### SCHEDULE

S.No.	Range	Income-tax Circles, Wards and Districts
1	2	3
4.	Special Range, Kanpur.	(i) Special Circle, Kanpur. (ii) Companies Circle, Kanpur. (iii) Fatehgarh Circle. (iv) Banda Circle (v) Central Circles III, IV and V, Kanpur.

Where an Income-tax Circle, Ward, or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax and Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner or Income-tax of the Range to whom that said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 8-9-75.

#### EXPLANATORY NOTE :

The amendment has become necessary consequent on changing over the jurisdiction over Central circles, Kanpur from A.A.C., Central Range, Meerut to A.A.C., Special Range, Kanpur.

(The above note does not form a part of notification but is intended to be merely clarificatory)

[No. 1075 (F. No. 261/1/75-ITJ)]

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1975

क्रा० प्रा० 5307.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपनी अधिसूचना सं० 708 (फा० सं० 261/1/74-प्राई० टी० जे०) तारीख 21-8-1974 से उपाध्व अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में, स्तम्भ 2 में, रोहतक रेंज से, सब (iv) में "नारनौल" का विलोप किया जाएगा और उसके स्थान पर "भिवानी" रखा जाएगा :

परन्तु आय-कर अधिकारी, नारनौल द्वारा पारित आदेशों की बाबत अधिकारिता भी सहायक आय-कर आयुक्त, रोहतक रेंज, रोहतक में निहित होगी ।

यह अधिसूचना 15-9-75 से प्रभावी होगी ।

[सं० 1081 (फा० सं० 261/17/75-प्राई० टी० जे०)]

New Delhi, the 15th September, 1975

S.O. 5307.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf the Central Board of Direct Taxes, hereby makes the following amendment in the Schedule appended to its Notification No. 708 (F. No. 261/1/74-ITJ) dated 21-8-1974 viz.

In the said Schedule from Rohtak Range in Column 2 at item (iv) "Narnaul" shall be deleted and in its place "Bhiwani" shall be substituted:

Provided that the jurisdiction in respect of the orders passed by the Income-tax Officer, Narnaul would also lie with Appellate Assistant Commissioner, Rohtak Range, Rohtak.

This Notification shall take effect from 15-9-1975.

### EXPLANATORY NOTE

The amendment has become necessary consequent upon the abolition of Narnaul Circle and creation of new office at Bhiwani w.e.f. 1-9-1975.

(The above note does not form a part of notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 1081(F. No. 261/17/75-ITJ)]

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1975

शुद्धि-पत्र

का० प्रा० 5308—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं० 1007 (का० सं० 261/4/75-आई०टी०जे०) तारीख 31-7-75 में,—

क्रम सं० 5 विशेष रेंज V, नई दिल्ली के सामने  
मध सं० (i)—विशेष सफिल; V, VI, VI, (प्रतिरिक्त), X, XII, XII, XIII, और XIV, नई दिल्ली में,  
“XII, XII” के स्थान पर “XI, XII” पढ़ें।

[सं० 1082(का० सं० 261/4/75-आई०टी०जे०)]

New Delhi, the 16th September, 1975

### CORRIGENDUM

S.O. 5308.—In the notification of the Central Board of Direct Taxes No. 1007 (F. No. 261/4/75-ITJ) dated 31-1-75.

Against Sl. 5 Special Range-V, New Delhi in Item No. (i) Special Circle, V. VI, VI(Adl.), X, XII, XII, XIII & XIV, New Delhi for “XII, XII” read “XI, XII”.

[No. 1082 (F. No. 261/4/75-ITJ)]

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1975

का० प्रा० 5309—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बोर्ड की अधिसूचना सं० 977 (का० सं० 261/9/75-आई० टी० जे०) तारीख 19 जुलाई, 1975 को आंशिक रूप से उपान्तरित करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश करता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आय-कर आयुक्त (अपील), उसके स्तम्भ 3 में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आय-कर सफिलों, बाइं और जिलों में आय-कर या अधिकार के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों और आज की भावत अपने कृत्यों का पालन करेंगे :—

### अनुसूची

क्रम सं०	रेंज	आय-कर बाइं
1	2	3
1. क-रेंज, मुम्बई		1. कम्पनी सफिल 1(1) से 1(5) तक 2. आई० टी० ओ०, विशेष सफिल 1, मुम्बई ; और 3. क-4 बाइं

1	2	3
2. ख-रेंज, मुम्बई		1. कम्पनी सफिल-1, सिबाय 1(1) से 1(5) तक केवल बाइं के 2. फिल्म सफिल 3. मुम्बई सफिल 4. आई० टी० ओ०, विशेष सफिल 2, मुम्बई ; और 5. ख-2 बाइं
3. ग-रेंज, मुम्बई		1. कम्पनी सफिल 2 2. ग-2 बाइं 3. निष्कांत सफिल 1 ; और 4. सम्पदा शुल्क सफिल
4. घ-रेंज, मुम्बई		1. कम्पनी सफिल 3 ; और 2. ग-बाइं
5. ङ-रेंज, मुम्बई		1. कम्पनी सफिल 4 2. बी०आर०सी० 3. एन० प्रार० प्रार० सी० ; और 4. विदेश धनुभाग
6. च-रेंज, मुम्बई		कम्पनी सफिल 5
7. छ-रेंज, मुम्बई		कम्पनी सफिल 6
8. ज-रेंज, मुम्बई		1. क-1 बाइं 2. क-5 बाइं ; और 3. टी० पी० सफिल
9. झ-रेंज, मुम्बई		1. क-3 बाइं 2. क-2 बाइं
10. ञ-रेंज, मुम्बई		1. ग-1 बाइं ; और 2. निष्क्रान्त सफिल 2
11. ट-रेंज, मुम्बई		1. बाजार बाइं 2. वेतन शाखा 1 ; और 3. वेतन शाखा 2
12. ठ-रेंज, मुम्बई		ख-3 बाइं
13. ड-रेंज, मुम्बई		1. ग-3 बाइं, और 2. ग-5 बाइं
14. ढ-रेंज, मुम्बई		घ-1 बाइं
15. ण-रेंज, मुम्बई		1. घ-2 बाइं ; और 2. ग-4 बाइं
16. त-रेंज, मुम्बई		1. बी० एस० डी० (पूर्व) ; और 2. बी० एस० डी० (वर्षा)
17. थ-रेंज, मुम्बई		1. ग-बाइं 2. हुण्डी सफिल अपील 3. ग-बाइं ; और

	4. ग क-वार्ड-1 से 7 तक केवल चार्ज
18. द-रेंज, मुम्बई	1. ड-वार्ड और 2. ग क-वार्ड, सिवाय 1 से 7 तक प्रभार के
19. घ-रेंज, मुम्बई	बी० एस० डी० (पश्चिम)

जहाँ कोई आय-कर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज को अन्तर्गत कर दिया जाता है, वहाँ उस आय-कर सर्किल, वार्ड या जिला या उसके भाग में किए गए निर्धारणों के फलस्वरूप होने वाली और उस रेंज के, जिससे वह आय-कर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तर्गत किया गया है, सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) के समक्ष इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पूर्व लम्बित अपीलें, उस तारीख से, जिसको यह अधिसूचना प्रभावी हो, उस रेंज के, जिसको उक्त सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तर्गत किया गया है, सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) को अन्तर्गत की जाएगी और उसके द्वारा उन पर कार्यवाही की जाएगी।

यह अधिसूचना 1-10-1975 से प्रभावी होगी।

[सं० 1093(फा० सं० 261/9/75-आई० टी० जे०)]

एस० रामस्वामी, अपर सचिव

#### INCOME-TAX

New Delhi, 24th September, 1975

S.O. 5309.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in partial modification of the Board's Notification No. 977 (F.No. 261/9/75-ITJ) dated the 19th July, 1975, the Central Board of Direct Taxes, hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Range specified in Column (2) of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and income assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts, specified in the corresponding entry in column (3) thereof:—

#### SCHEDULE

Sr.No.	Range	Income Tax Ward/Circle & District.
1	2	3
1. A-Range, Bombay		1. Companies Circle-I (1) to I (5) charges only 2. I.T.O. Special Circle I, Bombay and 3. A-IV Ward.
2. B-Range, Bombay		1. Companies Circle I except I (1) to I(5) charges only. 2. Film Circle. 3. Bombay Circle 4. I.T.O., Spl. Circle II, Bombay and 5. B-II Ward.
3. C-Range, Bombay		1. Companies Circle II 2. C-II Ward 3. Evacuees Circle I and 4. Estate Duty Circle.
4. D-Range, Bombay		1. Companies Circle III and 2. X-Ward.

Appellate Controller of Estate  
Duty-cum-A.A.C.

1	2	3
5. E-Range, Bombay		1. Companies Circle IV 2. B.R.C. 3. N.R.R.C. and 4. Foreign Section.
6. F-Range, Bombay		Companies Circle V.
7. G-Range, Bombay		Companies Circle VI
8. H-Range, Bombay		1. A-I Ward 2. A-V Ward and 3. T.P. Circle
9. I-Range, Bombay		1. A-III Ward and 2. A-II Ward
10. J-Range, Bombay		1. B-I Ward and 2. Evacuees Circle II.
11. K-Range, Bombay		1. Market Ward 2. Salaries Branch-I and 3. Salaries Branch-II.
12. L-Range, Bombay		B-III Ward.
13. M-Range, Bombay		1. C-III Ward and 2. C-V Ward.
14. N-Range, Bombay		D-I Ward.
15. O-Range, Bombay		1. D-II Ward and 2. C-IV Ward.
16. P-Range, Bombay		1. B.S.D. (East) and 2. B.S.D. (South)
17. Q-Range, Bombay		1. C-I Ward 2. Hundi Circle Appeals 3. G-Ward and 4. GA-Ward 1st to 7th Charges only.
18. R-Range, Bombay		1. E-Ward and 2. GA-Ward except 1st to 7th charges.
19. S-Range, Bombay		B.S.D. (West).

Where an Income-tax Circle Ward & District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date this Notification shall take effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 1-10-1975.

#### EXPLANATORY NOTE :

(The amendment has become necessary consequent on redistribution of work-load among A.A.C.s in Bombay charge).

(The above note does form part of notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 1093 (F. No. 261/9/75-ITJ)]

S. Ramaswamy, Under Secy.

बाणिज्य मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय,

प्रारोह

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1975

फा० आ० 5310.—सर्वश्री रेनवाक्सी लेबोरेट्रीज लि० नई दिल्ली को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से रिफ्रेमिसिन पाउडर के आयात के लिए 4,29,000 रुपये मूल्य का एक आयात लाइसेंस संख्या पी० डी० 1366112, दिनांक 27-2-75 प्रदान किया गया था। उन्होंने लाइसेंस की सीमाभूतक

निकासी प्रति की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है। यह भी उल्लेख किया गया है कि विषयाधीन सीमाशुल्क निकासी प्रति उपयोग किए बिना ही खो गई थी और वह किसी भी सीमाशुल्क समाहर्ता से पंजीकृत नहीं कराई गई थी।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथपत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस संख्या पी० डी० 1366112, दिनांक 27-2-75 की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है और निवेश देता है कि इसकी अनुलिपि उनको जारी की जानी चाहिए। लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति रद्द एतद्वारा की जाती है।

[सं० सी० एच/भार-5(6)/ए० एम०-75/भार० एम०-3/2373]

ए० एत० चटर्जी, उप-मुख्य नियंत्रक

# MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

## ORDER

New Delhi, the 1st December, 1975

**S.O. 5310.**—M/s. Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi, where granted Import Licence No. P/D/1366112 dated 27-2-1975 for Rs. 4,29,000 for import of Rifampicin Powder from G.C.A. They have requested for issue of duplicate Customs Purposes Copy of the licence on the ground that the original Custom Purposes Copy has been lost. It has further been stated that the Custom Purposes Copy in question was lost after utilizing Rupees Nil and that the same had not been registered with any of the Collectors of Customs.

In support of their contention, the applicant has filed an affidavit. The under signed is satisfied that the Original Customs Purposes Copy of licence No. P/D/1366112 dated 27-2-1975 has been lost and directs that duplicate Customs Purposes Copy of the said licence should be issued to them. The Original Customs Purposes copy of the licence is hereby Cancelled.

[Ref. No. Ch/R-5(6)/A. M. 75/R.M. 3/2373]

A. N. Chatterji, Dy. Chief Controller.

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय  
(केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र)

आदेश

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त, 1975

**का०आ० 5311.**—सर्वश्री वल्ला साइंटिफिक वर्क्स, 8, इन्डस्ट्रियल इस्टेट सोलन (हिमाचल प्रदेश) को अप्रैल-मार्च, 74 अवधि के लिये सामान्य मुद्रा क्षेत्र से अन्तिम उत्पाद साइक्रोस्कोपिक्स आदि के लिये संघटकों के आयात के लिये 16168 रु० का लाइसेंस सं० पी०/एस०/1805 288 दिनांक 30-3-74 स्वीकृत किया गया था।

2. पार्टी ने यह बताया है कि उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति बिना उपयोग किये और किसी भी पलन पर बिना पंजीकृत कराए ही खो गई / अस्थानस्थ हो गई है। और उसी को रद्द करने के लिये अनुरोध किया है। पार्टी ने उसी की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति जारी करने के लिये भी अनुरोध किया है। पार्टी ने उपर्युक्त बयान के समर्थन में आयात व्यापार नियंत्रण, नियम एवं क्रियाविधि हेतु 1975-76 की कठिना 320 में यथा प्रपेक्षित एक शपथ पत्र दाखिल किया है।

3. आयात नियंत्रण आदेश 1955 दिनांक 7 दिसम्बर, 1955 की धारा 9(सी०सी०) के अन्तर्गत प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग कर मैं लाइसेंस की उक्त सीमाशुल्क प्रति को रद्द करने का आदेश देता हूँ।

4. आवेदक को अब आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हेतु 1975-76 की कठिना 320(4) की व्यवस्था के अनुसार सामान्य मुद्रा क्षेत्र से उक्त लाइसेंस, मूल्य 16168 रु० की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति जारी की जा रही है।

[संख्या पी०/डी०-2(एन०)/ए०एम०-74/ए०यू० एच०एच०/सी०एल०ए०/1680]

## OFFICE OF THE JOINT CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS ORDER

New Delhi, the 5th August, 1975

**S.O. 5311.**—M/s. Dutta Scientific Works, 8, Industrial Estate Solan (HP) were granted licence No. P/S/1805298 dated 30-3-74 for Rs. 16168 on GCA for import of components for the end use Microscopies etc. for AM74 period.

2. The party have intimated that the customs purposes copy of the above said licence has been lost/misplaced without having been utilised and without having been registered at any port and have requested for cancellation thereof. Party have also requested to issue duplicate customs purposes copy of the same. The party have filed an affidavit in support of above statement as required vide para 320 of STU Hand Book of Rules and Procedure, 1975-76.

3. In exercise of the power conferred on me under section 9(cc) of Import Control Order 1955 dated 7th December, 1955, I order the cancellation of the foresaid customs purposes of copy of the licence.

4. The applicant is now being issued duplicate customs purposes copy of the aforesaid licence for Rs. 16168 on GCA in accordance with the provision of para 320(4) of the Hand Book of Rules and Procedure 1975-76.

[No. P/D-2(N)/AM-74/AU-HH/CLA/1680]

आदेश

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1975

**का०आ० 5312.**—सर्वश्री पटेल कारपोरेशन इन्डस्ट्रीज, 26-डी०एल०एफ० इन्डस्ट्रियल एरिया, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली को रुपये भुगतान क्षेत्र और यू०के० क्रेडिट से मशीन उपकरणों के लिये कच्ची सामग्री के आयात के लिये आयात लाइसेंस संख्या पी०/एस०/1697863 और पी०/एस०/1697865, दिनांक 30-4-71 क्रमशः 30,814 रु० और 11,808 रुपये मूल्य के लिये प्रदान किये गये थे। उन्होंने सूचना दी है कि इन लाइसेंसों की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रतियां बिलकुल भी उपयोग किये बिना ही खो गई /अस्थानस्थ हो गई हैं।

2. उपर्युक्त कथन की पुष्टि में फर्म ने आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक, 1975-76 के पैरा 320 के अन्तर्गत यथा प्रपेक्षित एक शपथपत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंसों की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रतियां खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं।

3. यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 के खंड-9(सी०सी०) द्वारा प्रवर्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं उक्त लाइसेंसों की उक्त मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रतियों को रद्द करने का आदेश देता हूँ।

[संख्या पी०/पी००४(एन०)/ए०एम०-74/ए०यू०यू०डी०/सी०एल०ए०/2853]

के० एन० कपूर, उप-मुख्य नियंत्रक,

उक्त संयुक्त-मुख्य नियंत्रक

## ORDER

New Delhi, the 1st October, 1975

**S.O. 5312.**—M/s. Patel Corporation Industries, 26-DLF Industrial Area, Najafgarh Road, New Delhi were granted import licences Nos. P/S/1697863 and P/S/1697865 dated 30-4-71 for Rs. 30,614 and Rs. 11,808 respectively from R.P.A. and U.K. Credit for import of Raw Materials for Machine Tools. They have reported that E.C. copies of the same have been lost/misplaced without having been utilised at all.

2. The firm has filed an affidavit in support of the above statement as required under Para 320 of I.T.C. Hand Book of Rules & Procedure, 1975-76. I am satisfied that the original Exchange Control copies of the above Licences have been lost/misplaced.

3. In exercise of the powers conferred on me under Section 9(cc) of Import Control Order 1955 dated 7-12-1955 as amended, I order the cancellation of the said original Exchange Control copies of the said licences.

[No. P/P-4(N)/AM-74/AU-UT/CLA/2853]

K. N. KAPOOR, Dy. Chief Controller  
for Jt. Chief Controller

आदेश

कलकत्ता, 22 अक्टूबर, 1975

**क्रा०प्रा० 5313.**—सर्वश्री धकोरिया इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा० लि०, 83, अघोरे सारणी, सोनारपुर, डा० राजपुर, 24 परगना, को 8,00,000 रुपये मूल्य का एक लाइसेंस सं० पी०/एस०/1774875/प्रा०/एम०एल०/50/सी०/37-38 दिनांक 19-2-74 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि प्रति के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति चुरा ली गई है। यह भी उल्लेख किया गया कि मूल लाइसेंस किसी भी कार्यालय में पंजीकृत नहीं किया गया है और लाइसेंस के पूर्ण मूल्य (अर्थात् 8,00,000 रुपये) का उपयोग करना बाकी है।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने इस संबंध में एक शपथ पत्र दाखिल किया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति चुरा ली गई है। मैं संतुष्ट हूँ कि लाइसेंस सं० पी०/एस०/1774875/प्रा०/एम०एल०/50/सी०/37-38 दिनांक 19-2-74 की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति चुरा ली गई है और निवेश देता हूँ कि इसकी अनुलिपि प्रति आवेदक को जारी की जानी चाहिये। लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति रद्द की जाती है।

[सं० ए०यू०/108992/6/ए०एम० 74/4/334]

## ORDER

Calcutta, the 22nd October, 1975

**S.O. 5313.**—M/s. Dhakuria Engineering Works Private Ltd., 83, Aghore Sarani, Sonarpur, P.O. Rajpur, 24-Parganas were granted licence No. P/S/1774875/R/ML/50/C/37-38 dated 19-2-1974 for Rs. 8,00,000. They have applied for duplicate customs purpose copy of the said licence on the ground that the original of the same has been stolen. It is further stated that the original licence has not been registered with any custom authorities and the full value of the licence (i.e. Rs. 8,00,000) remained unutilised.

In support of the contention the applicant has filed an affidavit to the effect that the original customs purpose copy of the licence has been stolen. I am satisfied that the original customs purpose copy of the licence No. P/S/1774875/R/ML/50/C/37-38 dated 19-2-1974 has been stolen and directed that a duplicate copy of the same should be issued to the applicant. The original customs purpose copy of the licence is cancelled.

[No. AU/108992/6/AM'74/IV/334]

आदेश

**क्रा०प्रा० 5314.**—सर्वश्री धकोरिया इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा० लि०, 83, अघोरे सारणी, सोनारपुर, डा० राजपुर, 24 परगना, को 24,00,000 रुपये मूल्य का एक लाइसेंस सं० पी०/एस०/1774874/सी०/एस०/एस०/50/सी०/37-38 दिनांक 19-2-74 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि प्रति के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति चुरा ली गई है। यह भी उल्लेख किया गया है कि लाइसेंस सीमाशुल्क कार्यालय, कलकत्ता में पंजीकृत किया गया है और उसका 6,23,166.50 रुपये की धनराशि के लिये आंशिक उपयोग किया गया है और उस पर 17,76,833.50 रुपये का उपयोग करना बाकी है।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक फर्म ने इस संबंध में एक शपथ पत्र दाखिल किया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति चुरा ली गई है। मैं संतुष्ट हूँ कि लाइसेंस सं० पी०/एस०/1774874/सी०/एस०/एस०/50/सी०/37-38 दिनांक 19-2-74 की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति 17,76,833.50 रुपये के लिये बिना उपयोग किये चुरा ली गई है और निवेश देता हूँ कि इस की अनुलिपि प्रति आवेदक को जारी की जानी चाहिये। लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति रद्द की जाती है।

[संख्या ए०यू०/108992/6/ए०एम'74/4/334]

के० पी० नारायण, उप-मुख्य नियंत्रक  
कुल संयुक्त मुख्य नियंत्रक

## ORDER

**S.O. 5314.**—M/s. Dhakuria Engineering Works Pvt. Ltd. 83, Aghore Sarani, Sonarpur, P.O. Rajpur, 24 Parganas were granted licence No. P/S/1774874/C/XX/50/C/37-38 dated 19-2-1974 for Rs. 24,00,000. They have applied for duplicate customs purpose copy of the said licence on the ground that the original of the same has been stolen. It is further stated that the licence has been registered with custom House, Calcutta and partly utilised for an amount of Rs. 6,23,166.50 and there remains unutilised balance of Rs. 17,76,833.50.

In support of this contention the applicant firm has filed an affidavit to the effect that the original custom purpose copy of the licence has been stolen. I am satisfied that the original custom purpose copy of the licence No. P/S/1774874/C/XX/50/C/37-38 dated 19-2-1974 for unutilised balance of Rs. 17,76,833.50 has been stolen and directed that a duplicate copy of the same should be issued to the applicant. The original custom purpose copy of the licence is cancelled.

[No. AU/108992/6/AM'74/IV/334]

K. P. NARAYAN, DY. Chief Controller  
for Jt. Chief Controller

आदेश

कोचीन, 26 सितम्बर, 1975

**क्रा०प्रा० 5315.**—सर्वश्री ग्रूरर कैमिकल्स (प्रा०) लि०, मंथरा रोड, कोचीन-2 को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से (1) पी०ए०मिनो फिनोल (2) थिओफिलीन (3) प्रयोगशाला रसायनों, एनेलिटिकल रिजेन्ट्स एवं (4) सिलीकॉन पोलिमर के आयात के लिये 4454 रुपये का एक आयात लाइसेंस सं० पी०/एल०/2644573/सी०/एस०/एस०/45/ई०/35-36/बी० 11.1 दिनांक 13-11-72 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के लिये इस आधार पर आवेदन

किया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति बिना उपयोग किये ी अस्थानस्थ हो गई है। अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस सं० पी०/एल०/2644573/सी०/एक्स०/एक्स०/45/बी० 11.1 दिनांक 13-11-72 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति अस्थानस्थ हो गई है और निवेश देता है कि उन्हें उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति जारी की जानी चाहिये। लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति इसके द्वारा रद्द की जाती है।

[आदेश सं० डी०सी०सी०/सी०एच०एन०/1/75 दिनांक 26-9-1975]

[मि०सं० बी०-3/आर०ई०पी०-2/जे०एस०-72 से जारी किया गया]

के० जयरामन, उप-मुख्य नियंत्रक

OFFICE OF THE DY. CHIEF CONTROLLER OF  
IMPORTS EXPORTS

Cochin, the 26th September, 1975

S.O. 5315.—M/s. Aroor Chemicals (P) Ltd. Manthra Road, Cochin-2 was granted licence No. P/L/2644573/C/XX/45/E/35-36/B. 11.1 dated 13-11-1972 for import (1) P. Amino Phenol (2) Theophylline (3) Laboratory Chemicals & Analytical Reagents and (4) Silicone Polymer from General Currency Area for a value of Rs. 4454. They have requested for the issue of a duplicate Customs purpose copy of the above licence on the ground that the original Customs purpose copy of the licence has been misplaced without utilising. In support of their contention, the applicant had filed an affidavit. The undersigned is satisfied that original Customs purpose copy of the licence No. P/L/2644573/C/XX/45/E/35-36/B. 11.1 dated 13-11-1972 has been misplaced and directs that duplicate customs purpose copy of the said licence should be issued to them. The original Customs purpose copy of the licence is hereby cancelled.

[Order No. DCC/CHN/1/75(Dt. 26-9-1975)]

[Issued for F. No. B. 3/REP.II/JS. 72]

K. JAYARAMAN, Dy. Chief Controller

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1975

का०आ०. 5316—यतः पेट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 175 तारीख 27-12-1974 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अतः, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एमद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्-द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में बंझित होने क बजाए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संघकों से मुक्त रूप में इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

डी०एस० नं० के०-159 से सी०बी०एफ० तक पाइपलाइन बिछाने के लिये

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कासोल

गांव	सर्वेक्षण नं०	हेक्टेयर	ऐमार्ह	से० टीयर
1	2	3	4	5
सेज	192	0	33	30
कार्ट ट्रैक		0	01	53
190/1		0	18	48
190/3		0	11	34
188/2		0	06	75
188/3		0	06	85
188/4		0	06	85
कार्ट ट्रैक		0	01	72
31/1		0	06	99
30/1		0	87	62
30/2		0	05	94
30/3		0	07	46
33/1		0	00	30
28		0	30	97
25/2/6		0	05	13
कार्ट ट्रैक		0	02	97
374/1		0	11	61
375/1		0	10	70
375/2		0	04	59
378/1		0	01	00
376/1		0	01	98
378/3		0	08	55
376/6		0	05	31
378/7		0	05	76
375/8		0	01	71
377/1/बी०		0	03	76
कार्ट ट्रैक		0	02	36
391/4		0	01	00
391/5		0	01	00
531		0	35	46
530/4		0	03	60
530/3		0	02	94
530/2		0	03	00
530/1		0	05	50
533		0	18	36
कार्ट ट्रैक		0	01	53
668/1		0	07	02
658		0	14	77
657/3		0	03	55
657/1		0	06	75

1	2	3	4	5
	655/2	0	08	01
	655/1	0	00	50
	653	0	07	67
	659/4 A	0	01	10
	659/2	0	04	85
	654/1/सी०	0	01	00
	654/1/सी०	0	03	04
	काटे ट्रैक	0	01	00
	681/2	0	01	00
	681/1	0	11	01
	681/3	0	02	22
	681/4	0	02	50
	682	0	05	00
	686/4	0	02	59
	683	0	05	27
	688/5	0	02	02
	688/3	0	02	00
	681/1	0	03	62
	712/सी०	0	26	39

[सं० 12016/7/74-एल०एण्ड एल०/1]

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS  
(Department of Petroleum)

New Delhi, the 26th November, 1975

**S.O. 5316.**—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O.No. 175 dated 27-12-74 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of Users in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

## SCHEDULE

FOR LAYING PIPELINE FROM D.S. No. K-159 TO CTF  
STATE : Gujarat Dist : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
SAIJ	192	0	33	30
	Cart Track	0	01	53
	190/1	0	18	42
	190/3	0	11	34
	188/2	0	06	75

1	2	3	4	5
	188/3	0	06	85
	188/4	0	06	85
	Cart Track	0	01	72
	31/1	0	06	99
	30/1	0	07	62
	30/2	0	05	94
	30/3	0	07	46
	33/1	0	00	50
	28	0	30	97
	25/2/6	0	05	13
	Cart Track	0	02	97
	374/1	0	11	61
	375/1	0	10	70
	375/2	0	04	59
	378/1	0	01	00
	376/1	0	01	98
	376/3	0	08	55
	376/6	0	05	31
	376/7	0	05	76
	376/8	0	01	71
	377/1/D	0	03	78
	Cart Trak	0	02	36
	391/4	0	01	00
	391/3	0	01	00
	531	0	35	46
	530/4	0	03	60
	530/3	0	02	94
	530/2	0	03	00
	530/1	0	05	50
	533	0	18	36
	Cart Track	0	01	53
	668/1	0	07	62
	658	0	14	77
	657/3	0	03	55
	657/1	0	06	75
	655/2	0	08	91
	655/1	0	00	50
	653	0	07	67
	659/4/A	0	01	10
	659/2	0	04	85
	654/1/B	0	01	00
	654/1/C	0	03	04
	Cart Track	0	01	00
	681/2	0	01	00
	681/1	0	11	01
	681/3	0	02	22
	681/4	0	02	50
	682	0	05	00
	686/4	0	02	59
	683	0	05	27
	688/5	0	02	02
	688/3	0	02	00
	688/1	0	03	62
	712/P	0	26	39

[No. 12016/7/74-L&amp;L/I]

कां०मा० 5317.—यतः पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना कां०मा० सं० 176 तारीख 27-12-1974 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।



अथ अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी संघकों से मुक्त रूप में इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

#### अनुसूची

सी०एम०नं० के०-166 से सी०टी०एफ० तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

राज्य : गुजरात जिला : कालोल तालुका : कालोल

गांव	मंथेक्षण नं०	हेक्टेयर	एअर ई	सं० टोयार
1	2	3	4	5
सेज	230	0	12	82
	229	0	10	65
	203	0	19	05
	204/2	0	08	02
	198/2	0	12	23
	198/1	0	01	58
	204/1	0	09	30
	197	0	04	65

[सं० 12016/7/74-एल०एंड०एल०/II]

S. O. 5317.—Whereas by a notification of the Govt. of Indian in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O.No. 176 dated 27-12-74 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

114GI/75-4

#### SCHEDULE

FOR LAYING PIPELINE FROM D.S. No. -K-166 TO CTF

State : Gujarat District : Kalol Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
SAJJ	230	0	12	82
	229	0	10	65
	203	0	19	06
	204/2	0	08	02
	198/2	0	12	23
	198/1	0	01	58
	204/1	0	09	30
	197	0	04	65

[No. 12016/7/74-L&L/II]

का०आ० 5318.—यतः पेट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 242 तारीख 9-1-1975 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार की पाइपलाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (i) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संघकों से मुक्त रूप में इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

#### अनुसूची

कूप नं० के 169 से सी०टी० एफ० तक पाइपलाइन बिछाने के लिये

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाणा तालुका : कालोल

गांव	प्लॉक नं०	हेक्टेयर	एअर ई	सेन्टायेर
1	2	3	4	5
चैशकल	323	0	06	37
	352	0	01	00
	353	0	15	07
	354	0	15	09
	355	0	04	30
	356	0	08	15

सर्वेक्षण नं०				
1	2	3	4	5
प्रमान्य	67 1/1	0	17	61
	662	0	01	00
	663	0	14	62
	664/2	0	07	87
	664/4	0	04	91
	666	0	06	78
	647	0	19	19
	648	0	01	00
	646	0	09	62
	कार्ट ट्रैक	0	00	50
	571/1	0	04	43
	571/10	0	08	25
	571/11	0	06	75
	571/12	0	09	97
	570/2	0	02	25
	570/3	0	05	10
	570/10	0	02	70
	570/5	0	04	87
	570/4	0	06	15
	553	0	06	37
	568	0	08	40
	569	0	01	00
	567	0	20	95
	365	0	09	75
झाक नं०				
प्रोला	474	0	13	13
	477	0	22	95
	कार्ट ट्रैक	0	01	95
	303	0	05	25
	302	0	26	40
	301	0	01	00
	कार्ट ट्रैक	0	01	00
	138	0	27	49
	139	0	06	30
	कार्ट ट्रैक	0	00	68
	141	0	32	80
	145	0	05	25
	122	0	09	59
	121	0	10	51
	117	0	00	50
	119	0	09	69
	118	0	09	90
	कार्ट ट्रैक	0	01	50
	64	0	09	75
	89	0	16	65
	87	0	10	05
	85	0	11	70
	71	0	16	12
	कार्ट ट्रैक	0	00	75
	82	0	11	63

1	2	3	4	5
	72	0	00	41
	73	0	07	75
	89	0	14	02
	कार्ट ट्रैक	0	01	27
	66	0	09	90
	85	0	08	62

[सं० 12016/15/74-एन० एंड एल०/1]

S. O. 5318.—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O.No. 242 Dated 9-1-75 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the Power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

## SCHEDULE

For laying pipeline from well No. K-169 to C.T.F.  
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
CHATRAL	323	0	06	37
	352	0	01	00
	353	0	15	07
	354	0	15	09
	355	0	04	30
	356	0	08	15
	Survey No.			
ISAND	674/1	0	17	61
	662	0	01	00
	663	0	14	62
	664/2	0	07	87
	664/4	0	04	91
	666	0	06	78
	647	0	19	19
	648	0	01	00
	646	0	09	62
	Cart-Track	0	00	50
	571/1	0	04	43
	571/10	0	08	25
	571/11	0	06	75
	571/12	0	09	97
	570/2	0	02	25
	570/3	0	05	10
	570/10	0	02	70
	570/5	0	04	87
	570/4	0	06	15
	553	0	06	37
	568	0	06	40
	569	0	01	00
	567	0	20	95
	565	0	09	75

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare	1	2	3	4	5
OIA	474	0	13	13					
	477	0	22	95		298	0	12	38
	Cart-Track	0	01	95		300	0	08	40
	303	0	05	25					
	302	0	26	40		301	0	21	56
	301	0	01	00		295	0	02	70
	Cart-track	0	01	00					
	138	0	27	49		302	0	02	02
	139	0	06	30		156	0	09	90
	Cart-Track	0	00	68					
	141	0	32	80		157	0	01	75
	145	0	05	25		158	0	11	20
	122	0	09	59					
	121	0	10	51		163	0	02	00
	117	0	00	50		162	0	15	96
	119	0	09	68					
	118	0	09	90		161	0	03	60
	Cart-Track	0	01	50					
	64	0	09	75		171/2	0	01	00
	89	0	16	65					
	87	0	10	05		171/1	0	11	70
	85	0	11	70		179/3	0	07	80
	71	0	16	12					
	Cart-Track	0	00	75		179/2	0	10	20
	82	0	11	63		179/1	0	12	98
	72	0	09	41					
	73	0	07	75		178	0	01	50
	89	0	14	02					
	Cart-Track	0	01	27		180	0	07	05
	86	0	09	90		184	0	06	45
	85	0	08	62					

[No. 12016/15/74-I. &amp; L/I]

का० आ० 5319.—यतः पेट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 28 तारीख 21-12-74 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार की पाइप लाइनों को विछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः मक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देनी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन विछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संशर्तों से मुक्त रूप में इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

डी० एस० नं० मानव 6 से मानव 4 तक पाइपलाइन विछाने के लिये				
राज्य : गुजरात	जिला : महसना	तालुका : कालोन्		
गांव	ब्लाक नं०	ट्रेक्टियर ऐग्राई	सेण्टीयर	
अधाना	310	0	01	87
	काट्ट ट्रेक	0	00	90

श्री

जिला : महसना  
महसना नं०

तालुका : कादी

1597	0	09	15
1598	0	08	03
काट्ट ट्रेक	0	02	55
1601	0	05	65
1602	0	12	33
1605	0	06	48
1604	0	06	00
1605/1	0	10	99
1605/2	0	04	80
1610	0	20	32
1386/3	0	03	00
1386/2	0	01	28
1386/1	0	02	40
1385/3	0	02	25
1385/2	0	02	48
1385/1	0	04	65
1390/2	0	01	50
1390/3	0	05	70
1391	0	01	13
1384/1	0	02	00
1384/2	0	08	33
1354	0	01	00
1383/2	0	00	50
1383/1	0	05	65

2	3	4	5
1382	0	04	50
1381	0	03	75
1374	0	10	05
1372/1	0	03	00
1372/2	0	04	13
1373/1	0	06	75
1363/2	0	08	48
1363/1	0	06	68
1295	0	10	66
1296/1/2	0	07	95
1302/1	0	05	85
1302/2	0	06	83
1272	0	05	55
1273/1/2	0	08	33
1274	0	04	13
1275	0	09	45
1134/1	0	02	33
1123	0	05	10

[सं० 12016/15/74-एल० एण्ड एल/II]

**S.O.5319.**—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 28 Dated 21-12-74 under sub-section (I) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (59 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines.

And Whereas the Competent Authority has under sub-section (I) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And Further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the Power conferred by the sub-section (I) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

#### SCHEDULE

FOR LAYING PIPELINE FROM D.S. No. SANAD-6  
TO SANAD-4

STATE : GUJARAT DISTRICT : MEHSANA TALUKA :  
KALOL

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Adhana	310	0	01	87
	Cart-Track	0	00	90
	298	0	12	38
	300	0	08	40
	301	0	21	56
	295	0	02	70
	302	0	02	02

1	2	3	4	5
	156	0	09	90
	157	0	01	73
	158	0	11	20
	163	0	02	00
	162	0	13	96
	161	0	03	60
	171/2	0	01	00
	171/1	0	11	70
	179/3	0	07	80
	179/2	0	10	20
	179/1	0	12	98
	178	0	01	50
	180	0	07	05
	184	0	06	45
	183	0	05	03
	188	0	18	90
	110	0	01	00
	189	0	15	01
	106	0	03	75
	105	0	14	33
	Cart-Track	0	00	68

THOL DISTRICT : MEHSANA  
Survey No.

TALUKA : KADI

1597	0	09	15
1598	0	08	03
Cart-Track	0	02	55
1601	0	05	63
1602	0	12	53
1603	0	06	48
1604	0	06	00
1605/1	0	10	99
1605/2	0	04	80
1610	0	20	32
1386/3	0	03	00
1386/2	0	01	28
1386/1	0	02	40
1385/3	0	02	25
1385/2	0	02	48
1385/1	0	04	65
1390/2	0	01	50
1390/3	0	05	70
1391	0	04	13
1384/1	0	02	00
1384/2	0	08	33
1354	0	01	00
1383/2	0	00	50
1383/1	0	05	65
1382	0	04	50
1381	0	03	75
1374	0	10	05
1372/1	0	03	00
1372/2	0	04	13
1373/1	0	06	75
1363/2	0	08	48
1363/1	0	06	68
1295	0	10	66
1296/1/2	0	07	95
1302/1	0	05	85
1302/2	0	06	83
1272	0	05	55
1273/1/2	0	08	33
1274	0	04	13
1275	0	09	45
1124/1	0	02	33
1123	0	05	10

[No. 12016/15/74-1. &amp; L/II]

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1975

कां०आ० 5320.—यतः पेट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना कां०आ० सं० 29 तारीख 23-12-1974 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को विद्युत के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपनता आशय घोषित कर दिया था।

और यतः मक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन विद्युत के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संघकों से सुकन रूप में इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

गेलिकी जी० जी० एस० नम्बर 2 से चन्द्रमागर-लकवा ट्रंक पाइप लाइन का जंकसन पाइन्ट तक की पाइप लाइन

राज्य : छत्तिस	जिला : शिवगागर	तालुक : आतखेत		
ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	गैरे सेन्टी गैरे	
1	2	3	4	5
हुडुपारा	68 ख	0	1	87
	68 ग	0	2	41
	149 ख	0	1	61
	150 ख	0	9	10
	154 ख	0	5	89
	254 ख	0	3	75
	254 ग	0	5	89
	255 क	0	4	95
	258 ख	0	3	75
	263 क	0	4	28
	266 ख	0	1	34
	268 ख	0	14	24
	269 ख	0	1	82
	270 ख	0	2	54
	351 ख	0	3	21
	352 ख	0	0	13
	353 ख	0	6	69
	355 ख	0	2	68
	356 ख	0	2	14
	357 ख	0	3	88
	358 ख	0	4	01
	359 ख	0	3	08

1	2	3	4	5
	361 ख	0	1	47
	480 ख	0	3	61
	481 ख	0	6	29
	482 ख	0	3	61
	483 ख	0	4	01
	484 ख	0	2	41
	485 ख	0	3	21
	486 ख	0	3	21
	487 ख	0	4	01
	488 ख	0	1	31
	519 ख	0	14	18
	526 ख	0	13	51
	528 ख	0	1	61
	529 ख	0	3	34
	535 ख	0	8	96
	536 ख	0	3	48
	537 ख	0	0	27
	543 ख	0	4	28
	544 ख	0	0	27
	545 ख	0	6	42
	546 ख	0	0	67
	720 ख	0	0	13
	721 ख	0	0	13
	723 ख	0	4	82
	754 ख	0	2	54
	882 ख	0	1	87
	881 ख	0	33	45
	885 ख	0	2	54
	886 ख	0	2	81
	888 ख	0	2	81
	899 ख	0	4	41
	900 ख	0	0	94
	901 ख	0	6	96
	913 ख	0	2	01
	407 ख	0	8	96
नराखोवा	408 ख	0	4	01
	409 ख	0	3	88
	410 ख	0	5	75
	414 ख	0	1	07
	415 ख	0	3	61
	431 ख	0	1	07
	443 ख	0	3	75
	444 ख	0	1	34
	446 ख	0	3	21
	457 ख	0	13	11
	456 ख	0	0	27
	458 ख	0	3	34
	480 ख	0	1	87
	481 ख	0	2	94
	483 ख	0	3	75
	489 ख	0	2	14
	495 ख	0	3	88
	497 ख	0	20	07
	499 ख	0	2	14

New Delhi the 5th December, 1975

**S.O. 5320.**—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 29 dated 23-12-74 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And Whereas the competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And Further Whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now Therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And Further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest in this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

**PIPELINE FROM GELEKI GGS NO. 2 TO JUNCTION POINT OF RUDRASAGAR LAKWA TRUNK PIPELINE  
STATE : ASSAM DISTRICT : SIBSAGAR TALUK :  
ATHKHEL**

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi- ares
1	2	3	4	5
Hudupara	68 Kha	0	1	87
	68 Ga	0	2	41
	149 Kha	0	1	61
	150 Kha	0	9	10
	154 Kha	0	5	89
	234 Kha	0	3	75
	254 Ga	0	5	89
	255 Ka	0	4	95
	258 Kha	0	3	75
	263 Ka	0	4	28
	266 Kha	0	1	34
	268 Kha	0	11	24
	269 Kha	0	4	82
	270 Kha	0	2	54
	351 Kha	0	3	21
	352 Kha	0	0	13
	253 Kha	0	6	69
	355 Kha	0	2	68
	256 Kha	0	2	14
	357 Kha	0	3	88
	358 Kha	0	4	01
	359 Kha	0	3	08
	361 Kha	0	1	47
	480 Kha	0	3	61
	481 Kha	0	6	29
	482 Kha	0	3	61
	483 Kha	0	4	01
	484 Kha	0	2	41
	485 Kha	0	3	21
	486 Kha	0	3	21
	487 Kha	0	4	01
	488 Kha	0	1	34
	519 Kha	0	14	18
	526 Kha	0	13	51
	528 Kha	0	1	61

1	2	3	4	5
	529 Kha	0	3	34
	535 Kha	0	8	96
	536 Kha	0	3	48
	537 Kha	0	0	27
	543 Kha	0	4	28
	544 Fha	0	0	27
	545 Kha	0	6	42
	546 Kha	0	0	67
	720 Kha	0	0	13
	721 Kha	0	0	13
	723 Kha	0	4	82
	754 Kha	0	2	54
	882 Kha	0	1	87
	884 Kha	0	33	45
	885 Kha	0	2	54
	886 Kha	0	2	81
	888 Kha	0	2	81
	899 Kha	0	4	41
	900 Kha	0	0	94
	901 Kha	0	6	96
	913 Kha	0	2	01
	914 Kha	0	2	81
Borakhowa	407 Kha	0	8	96
	408 Kha	0	4	01
	409 Kha	0	3	88
	410 Kha	0	5	75
	414 Kha	0	1	07
	415 Kha	0	3	61
	431 Kha	0	1	07
	443 Kha	0	3	75
	444 Kha	0	1	34
	446 Kha	0	3	21
	457 Kha	0	13	11
	456 Kha	0	0	27
	458 Kha	0	3	34
	480 Kha	0	1	87
	481 Kha	0	2	94
	483 Kha	0	3	75
	489 Kha	0	2	14
	495 Kha	0	3	88
	497 Kha	0	20	07
	499 Kha	0	2	14

[12019/2/74-L. &amp;1.]

**गुडि-पत्र**

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1975

**क्रा० आ० 5321.**—आसाम राज्य के जिला सिबसागर में गलेकी जी० जी० एस० संख्या 2 के रुद्रासागर—लक्वा ट्रंक पाइप लाइन के जंकशन प्वायन्ट तक पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग का अधिकार अर्जन करने हेतु भारत के राजपत्र भाग-ii खण्ड 3(1) दिनांक 4-1-1975 के अन्तर्गत प्रकाशित पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की सरकारी अधिसूचना के माध्यम से संख्या 12019/2/74-एल एण्ड एस/दिनांक 23-12-74 में गांव हुदुपरा के सामने 256 खा के स्थान पर 356 खा पड़े।

पड़े

के लिये

356 खा

256 खा

[सं० 12019/2/74-एल तथा एस]

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 5th December, 1975

**S.O. 5321.**—In schedule appended to the Govt. Notification, Ministry of Petroleum & Chemicals, Department of Petroleum, New Delhi, No. 12019/2/74-L&L/1 dated 23-12-74 published under Section 3(1) at page 56 of the Gazette of India dt. 4-1-75 Part II for the Acquisition Right of User for laying pipeline from Gelleky GGS No. 2 to Junction point of Rudra-sagar-Lakwa trunk pipeline in Assam State, Dist. Sibsagar.

Read	For
356 kha against the village Hudupara.	256 kha

[No. 12019/2/74-L&amp;L]

## पुद्धि-पत्र

का० आ० 5322.—पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना संख्या 12019/2/74-एल एण्ड एल/4 दिनांक 23-12-74 का०आ० 32 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र भाग ii खण्ड 3 उप-खण्ड (ii) दिनांक 4-1-1975 के पृष्ठ संख्या 59 में गांव नापुवगौटी तालुका अथखोल जिला सिबसागर पर्व के स्थान पर

सर्वेक्षण नं०	हेक्टेयर	ए. आर. ए. आर. सर्वेक्षण नं०	हेक्टेयर	ए. आर. ए. आर.
	ई पी ई		ई पी ई	
2143/खा	0 1 61	2135/खा	0 7 09	
2142/खा	0 10 57	2144/खा	0 18 06	
2024/खा	0 8 03	2143/खा	0 22 34	
		1604/खा	0 6 15	
		2147/खा	0 1 61	

[सं० 12019/2/74-एल तथा एल]

टी० पी० मुब्रहामनियन, अवर सचिव

## CORRIGENDUM

**S.O. 5322.**—In the notification of Government of India in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Department of Petroleum) No. 12019/2/74-L&L/IV Dated, 23-12-74 under S.O. 32 in the Gazette of India, Part II section 3 Sub-section (ii) dated 4-1-75 page Nos. 59.

Village Napumbaurah Taluka Athkhel Distt. Sibsagar  
Read For

Survey No.	Hectare	Are P. Are	Survey Hectare	Are P. Are
2143/kha—0—1—61			2135/kha—0—7—09	
2142/kha—0—10—57			2144/kha—0—18—06	
2024/kha—0—8—03			2143/kha—0—22—34	
			1604/kha—0—6—15	
			2147/kha—0—1—61	

[No. 12019/2/74-R&amp;L]

P. SUBRAHMANYAN, Under Secy

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1975

का० आ० 5323.—कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 505(अ), तारीख 12 सितम्बर, 1975 द्वारा, केन्द्रीय

सरकार ने इस अधिसूचना में उपाखण्ड अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 5920.00 एकड़ (लगभग) या 2395.71 हेक्टेयर (लगभग) भूमियों में कोयले के लिए पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमियों के भाग में कोयला अभिप्राय्य है;

अतः, अब, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इससे उपाखण्ड अनुसूची में वर्णित 2655.00 एकड़ (लगभग) या 1074.42 हेक्टेयर (लगभग) की भूमियों को अर्जित करने के अपने आशय की सूचना देती है।

2. इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण उपायुक्त, गिरीडीह (बिहार) के कार्यालय में या कोयला निगलक के कार्यालय, 1, कार्डिनल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता में या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) के कार्यालय, बरभंगा हाउस रांची (बिहार) में किया जा सकेगा।

3. कोयला निगलक, 1, कार्डिनल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता को केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम के अधीन सशम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

## अनुसूची

नया कारो खंड

उप-खंड 'क'

पूर्वी बोकारो कोयला क्षेत्र

जिला गिरीडीह

डा० सं० रा०/41/75

6 अक्टूबर, 1975

(जिनमें अर्जित की जाने वाली भूमियां वर्णित की गई हैं)

## मधी अधिकार

क्रम संख्या	ग्राम	थाना संख्या	थाना	जिला	क्षेत्र टिप्पणियां
1.	गोविन्दपुर	नन्नाडीह (बरसी)	15	गिरिडीह	-- भाग
2.	कुपनिया	"	17	"	-- "
3.	बस्सी	"	18	"	-- "
4.	जरिडीह	"	19	"	-- "

कुल क्षेत्र:—2045.00 एकड़ (लगभग)

या:— 817.57 हेक्टेयर (लगभग)

गोविन्द पुर ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक:—2462(पी), 2463(पी), 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476(पी), 2477 से 2526, 2527(पी), 2550(पी), 2551(पी), 2552, 2553(पी), 2554(पी), 2558(पी), 2559(पी), 2560(पी), 2561 से 2565, 2566(पी), 2567(पी), 2568(पी), 2572(पी), 2600(पी), 2674(पी), 2685(पी), 2686, 2687(पी), 2688 से 2691, 2692 (पी), 2698, 2699, 2701 से 2762, 2765(पी), 2766(पी), 2767(पी), 2768 और 2769(पी)।

कुर्पानिया ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक:—1(पी), 9(पी), 14(पी), 15, 16(पी), 17, 18, 19(पी), 20(पी), और 42(पी),

बरमो ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक:—178(पी), 189(पी), 190 से 195, 196(पी), 198(पी), 199(पी), 200(पी), 201(पी), 202, 203(पी), 204(पी), 221(पी), 222(पी), 224(पी), 227(पी), 228(पी), 229, 230(पी), 231 से 262, 263(पी), 264(पी), 265 से 296, 297(पी), 298(पी), 299(पी), 301(पी), 302(पी), 304(पी), 305(पी), 306(पी), 342(पी), 802(पी), 803(पी) और 1386 (पी)।

जरिडीह ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक:—287(पी), 288(पी), 290(पी), 672(पी), 674(पी), 695(पी), 696, 697(पी), 698(पी), 699(पी), 701(पी), 702 से 718, 719(पी) और 720(पी)।

सीमा वर्णन

ए-बी लाइन गोबिन्दपुर ग्राम में [जो कोयला अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन अधिसूचित गोबिन्दपुर खण्ड की आंशिक सामान्य सीमा भी है [प्लॉट सं० 2462, 2476, 2527, 2550, 2551, 2553, 2554, 2558, 2560, 2559, 2572, 2567, 2568, 2566, 2527, 2600, 2687, 2585, 2600 और 2674 से हटा कर जाती है और 'बी' बिन्दु पर मिलती है।

बी-सी लाइन गोबिन्दपुर ग्राम में प्लॉट सं० 2692, 2765, 2692, 2765, 2767, 2769, 2767 से होकर, बरमो ग्राम में प्लॉट सं० 196, 199, 200, 201, 203, 204, 196, 221, 230, 222, 224, 230, 227 और 288 से होकर जरिडीह ग्राम में (जो रेल लाइन की आंशिक उत्तरी सीमा भी है) प्लॉट सं० 287, 288, 290, 695, 697, 698, 699, 701, 674, 672 और 720 से होकर जाती है और 'सी' बिन्दु पर मिलती है।

सी-डी लाइन जरिडीह ग्राम में प्लॉट सं० 720 और 719 से होकर बरमो ग्राम में (जो राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की बोकारो कोयला खान की आंशिक पश्चिमी सीमा भी है) प्लॉट सं० 304, 305, 306, 304, 302, 301, 298, 298, 299, 264, 263, 342, 178, 802, 803, और 178 से होकर जाती है और 'डी' बिन्दु पर मिलती है।

डी-ई-एफ-जी-एच लाइन बरमो ग्राम में प्लॉट सं० 178, 189 और 196 से कुर्पानिया ग्राम में प्लॉट सं० 42, 20, 19, 9, 16 और 14 से होकर, तत्पश्चात् प्लॉट सं० 1 की आंशिक पूर्वी सीमा के साथ-साथ तथा प्लॉट सं० 1 से होकर जाती है और 'एच'-बिन्दु पर मिलती है।

एच-ए लाइन गोबिन्दपुर ग्राम में प्लॉट सं० 2766, 2767, 2765, 2463 और 2462 से होकर जाती है और आरम्भिक 'ए' बिन्दु पर मिलती है।

उप-खण्ड 'ख'

सभी अधिकार

क्रम संख्या	ग्राम	थाना संख्या	थाना संख्या	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
-------------	-------	-------------	-------------	------	---------	------------

1.	बरमो	नवाडीह (बरमो)	19	गिरिडीह	--	भाग
----	------	---------------	----	---------	----	-----

कुल क्षेत्र:—285.00 एकड़ (लगभग)

या:—115.33 हेक्टेयर (लगभग)

बरमो ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक:—11(पी), 12 से 15, 16(पी), 17, से 22, 23(पी), 36(पी), 40(पी), 48(पी), 49, 50, 51 और 1392 (पी),

सीमा वर्णन

आई-जे लाइन बरमो ग्राम में प्लॉट सं० 11 और 1392 से होकर जाती है और 'जे' बिन्दु पर मिलती है।

जे-के लाइन गोदी नदी की आंशिक मध्य रेखा के साथ-साथ, जो बरमो और कुर्पानिया ग्रामों की आंशिक सामान्य सीमा भी है, जाती है और 'के' बिन्दु पर मिलती है।

के-एल लाइन बरमो ग्राम में जो, भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन अर्जित क्षेत्र के साथ आंशिक सामान्य सीमा भी है, प्लॉट सं० 1392, 48, 36, 40, 36, और 23 से होकर जाती है और 'एल' बिन्दु पर मिलती है।

एल-एम लाइन बरमो ग्राम के प्लॉट सं० 23 और 27 के आंशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है और 'एम' बिन्दु पर मिलती है।

एम-आई लाइन बरमो ग्राम में प्लॉट सं० 23, 16 और 11 से होकर जाती है और आरम्भिक 'आई' बिन्दु पर मिलती है।

उप-खण्ड 'ग'

सभी अधिकार

क्रम संख्या	ग्राम	थाना संख्या	थाना संख्या	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
-------------	-------	-------------	-------------	------	---------	------------

1.	बैदकारो	नवाडीह (बरमो)	20	गिरिडीह	--	भाग
2.	करगाली	"	66	"	--	"

कुल क्षेत्र:—325.00 एकड़ (लगभग)

या:—131.52 हेक्टेयर (लगभग)

बैदकारो ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक:—9(पी), 35(पी), 38(पी), 39, 40(पी), 41(पी), 42(पी), 43 से 55, 56(पी), 57(पी) और 64(पी)

करगाली ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक:—1(पी)।

सीमा वर्णन

एन-ओ-पी लाइन बैदकारो ग्राम में प्लॉट सं० 9, 38, 41, 42, 9 और 35 से होकर जाती है और 'पी' बिन्दु पर मिलती है।



पी-क्यू लाइन बेदकारो ग्राम में (जो भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन अर्जित क्षेत्र के साथ आंशिक मामान्य सीमा भी है) प्लॉट सं. 35, 9 और 64 से होकर जाती है और 'क्यू' बिन्दु पर मिलती है।

क्यू-आर लाइन बेदकारो ग्राम में प्लॉट सं. 64 और करगाली ग्राम में प्लॉट सं. 1 से होकर जाती है और 'आर' बिन्दु पर मिलती है।

आर-एस लाइन करगाली ग्राम में प्लॉट सं. 1 होकर और बेदकारो ग्राम में प्लॉट सं. 64 और 57 से होकर जाती है 'एस' बिन्दु पर मिलती है।

एस-टी-एन लाइन बेदकारो ग्राम में प्लॉट सं. 57, 56 और 9 से होकर जाती है और आरम्भिक 'एन' बिन्दु पर मिलती है।

[सं. 19(29)/75 गैल]

एस० आर० ए० रिक्की, उप सचिव

# MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 26th Nov., 1975

**S.O. 5323.**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 505(E) dated the 12th September, 1975, under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 5920.00 acres (approximately) or 2395.71 hectares (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule appended to that notification.

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in part of the said lands;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the lands measuring 2655.00 acres (approximately) or 1074.42 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto.

2. The plans of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Giridih (Bihar) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the office of the National Coal Development Corporation Limited (Revenue Section) Darbhanga House Ranchi (Bihar).

3. The Coal Controller, 1 Council House Street, Calcutta has been appointed by the Central Government as the competent authority under the Act.

## THE SCHEDULE

New Karo Block  
Sub-Block 'A'  
East Bokaro Coalfield  
District Giridih  
Drg. No. Rev/41/75  
Dated 6-10-1975  
(Showing lands to be acquired)

All Rights

S. Village No.	Thana	Thana Number	District	Area	Remarks
1. Gobindpur	Nawa-dih (Bermo)	15	Giridih	..	Part
2. Kurpania	..	17	..	..	..
3. Bermo	..	18	..	..	..
4. Jaridih	..	19	..	..	..

Total area : 2045.00 acres (approximately)  
or 827.57 hectares (approximately)

Plot numbers to be acquired in village Gobindpur:—2462(P), 2463(P), 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476(P), 2477 to 2526 2527(P), 2550(P), 2551(P), 2552, 2553(P), 2554(P), 2558(P), 2559(P), 2560(P), 2561 to 2565, 2566(P), 2567(P), 2568(P), 2572(P), 2600(P), 2674(P), 2685(P), 2686, 2687(P), 2688 to 2691, 2692(P), 2698, 2699, 2701 to 2762, 2765(P), 2766 (P), 2767(P), 2768 and 2769(P).

Plot numbers to be acquired in village Kurpania:—1(P), 9(P), 14(P), 15, 16(P), 17, 18, 19(P), 20(P) and 42(P).

Plot numbers to be acquired in village Bermo:—178(P), 189(P), 190 to 195, 196(P), 198(P), 200(P), 201(P), 202, 203(P), 204(P), 221(P), 222(P), 224(P), 227(P), 228(P), 229, 230(P), 231 to 262, 263(P), 264(P), 265 to 296, 297(P), 298(P), 299(P), 301(P), 302(P), 304(P), 305(P), 306(P), 342(P), 802(P), 803(P) and 1386.

Plot numbers to be acquired in village Jaridih:—287(P), 288(P), 290(P), 672(P), 674(P), 695(P), 696, 697(P), 698(P), 699(P), 701(P), 702 to 718, 719(P), and 720(P).

## BOUNDARY DESCRIPTION :

A—B line passes through plot nos. 2462, 2476, 2527, 2550, 2551, 2554, 2553, 2554, 2558, 2560, 2559, 2572, 2567, 2568, 2566, 2527, 2600, 2687, 2685, 2600 & 2674 in village Gobindpur (which is also the part common boundary of Gobindpur Block notified under 4(1) of the Coal Act) and meets at point 'B'.

B—C line passes through plot numbers 2692, 2765, 2692, 2765, 2767, 2769, 2767, in village Gobindpur through plot numbers 196, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 196, 221, 230, 222, 224, 230, 227 and 228 in village Bermo through plot numbers 287, 288, 290, 695, 697, 698, 699, 701, 674, 672 and 720 in village Jaridih (which is also the part northern boundary of Railway line) and meets at point 'C'.

C—D line passes through plot numbers 720 and 719 in village Jaridih through plot numbers 304, 303, 306, 304, 302, 301, 298, 297, 299, 264, 263, 342, 178, 802, 803 and 178 in village Bermo (which is also the part western boundary of NCDC's Bokaro Colliery) and meets at point 'D'.

D—E  
F—G

lines pass through plot numbers 178, 189 and 196 in village Bermo through plot numbers 42, 20, 19, 9, 16 & 14 then along part eastern boundary of plot no. 1 and through plot no. 1 in village Kurpania and meet at point 'H'.

H—A line passes through plot numbers 2766, 2767, 2765, 2463 and 2462 in village Gobindpur and meets at a starting point 'A'.

Sub-Block 'B'				
All Rights	S. Village No.	Thana	Thana Number	District Area Re-marks
	1. Bermo	Nawa-dih (Bermo)	18	Giri-dih Part

Total area :—285.00 acres (approximately).  
or 115.33 hectares (approximately).

Plot numbers to be acquired in village Bermo :—11(P), 12 to 15, 16(P), 17 to 22, 23(P), 36(P), 40(P), 48(P), 49, 50, 51 & 1392(P).

#### BOUNDARY DESCRIPTION :—

- I=J line passes through plot no. 11 and 1392 in village Bermo and meets at point 'J'.  
J=K line passes along the part central line of Godo Nadi which is also the part common boundary of villages Bermo and Kurpania and meets at point 'K'.  
K=L line passes through plot numbers 1392, 48, 36, 40, 36, and 23 in village Bermo which is also the part common boundary with the area acquired under L.A. and meets at point 'L'.  
L=M line passes along the part common boundary of plot nos. 23 & 27 in village Bermo and meets at point 'M'.  
M=I line passes through plot numbers 23, 16 and 11 in village Bermo and meets at starting point 'I'.

Sub-Block 'C'				
All Rights	S. Village No.	Thana	Thana Number	District Area Re-marks
	1. Baidkaro	Nawa-dih (Bermo)	20	Giri-dih Part
	2. Kargali	"	66	" "

Total area : 325.00 acres (approximately)  
or 131.52 hectares (approximately)

Plot numbers to be acquired in village Baidkaro :—9(P), 35(P), 38(P), 39, 40, 41(P), 42(P), 43 to 55, 56(P), 57(P), & 64 (P).  
Plot numbers to be acquired in village Kargali :—1(P).

#### BOUNDARY DESCRIPTION:

- N=O=P line passes through plot numbers 9, 38, 41, 42, 9 and 35 in village Baidkaro and meet at point 'P'.  
Q=Q line passes through plot numbers 35, 9 and 64 in village Baidkaro (which is also the part common boundary with the area acquired under L.A. Act) and meets at point 'Q'.  
Q=R line passes through plot no. 64 in village Baidkaro and plot no. 1 in village Kargali and meets at point 'R'.  
R=S line passes through plot no. 1 in village Kargali and through plot nos. 64 and 57 in village Baidkaro and meets at point 'S'.

S=T=N lines pass through plot numbers 57, 56 and 9 in village Baidkaro and meets at starting point 'N'.

[No. 19(29)/75-CEL]

S.R.A. RIZVI, Dy. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1975

का० आ० 5324.—केन्द्रीय सिल्क बोर्ड अधिनियम 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उपधारा (3) के अनुच्छेद (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा वस्तु आयुक्त

वाणिज्य मंत्रालय सरकार को हम अधिसूचना के जारी होने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए केन्द्रीय सिल्क बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है।

[फाइल संख्या 6/24/75-सी० एण्ड एम०]

एस० एन० घोष, उप निदेशक

#### MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Deptt. of Industrial Development)

New Delhi, the 25th November, 1975

S.O. 5324.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-Section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act 1948 (61 of 1948) the Central Government hereby appoints the Textile Commissioner, Ministry of Commerce, Government of India as a Member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of issue of this notification.

[File No. 6/24/75/C&S]

S. N. GHOSH, Dy. Director

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1975

का० आ० 5325.—केन्द्रीय सरकार अधिनियम संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन दी सेन्ट्रल इंडिया कमर्शियल एक्सचेंज लि० ग्वालियर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को गुड की अधिनियम संविदाओं के बारे में 26 नवम्बर 1975 से 25 नवम्बर 1976 (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की एक वर्ष की अनिश्चित कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[सं० 12(21)-आई०टी०/75]

(Department of Civil Supplies & Cooperation)

New Delhi, the 26th November, 1975

S.O. 5325.—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Central India Commercial Exchange Limited, Gwalior, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of one year from the 26th November, 1975 to the 25th November, 1976 (both days inclusive) in respect of forward contracts in gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(21)-IT/75]

का० प्रा० 5326.—केन्द्रीय सरकार अधिम संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन कानपुर कमोडिटी एक्सचेंज लि०, कानपुर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किये गये आवेदन पर बायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को गुड़ की अधिम संविदाओं के बारे में 26 नवम्बर 1975 से 25 नवम्बर 1976 (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की एक वर्ष की अनिश्चित कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो बायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[सं० 12(22)—आई० टी०/75]

S.O. 5326.—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Kanpur Commodity Exchange Ltd., Kanpur, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of one year from the 26th November, 1975 to the 25th November, 1976 (both days inclusive) in respect of forward contracts in gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(22)-IT/75]

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1975

का० प्रा० 5327.—केन्द्रीय सरकार अधिम संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन हांसी पंजाब कमर्शियल एक्सचेंज लि० हांसी द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किये गये आवेदन पर बायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को विनोद की अधिम संविदाओं के बारे में 13 जनवरी 1976 से 12 जनवरी 1977 (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की एक वर्ष की अनिश्चित कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो बायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[सं० 12(23)—आई० टी०/75]

ए० मुंबई, निदेशक

New Delhi, the 27th November, 1975

S.O. 5327.—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Hansi Punjab Commercial Exchange Ltd., Hansi, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period

of one year from the 13th January, 1976 to the 12th January, 1977 (both days inclusive) in respect of forward contracts in cottonseed.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(23)-IT/75]

A. MUBAYI, Director

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय  
(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1975

का० प्रा० 5328.—यतः भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे लिखे विश्वविद्यालयों ने उनके समक्ष लिखी तारीख से भारतीय चिकित्सा परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया है: अर्थात्

व्यक्ति का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	निर्वाचन की तारीख
1. प्रो० ए० एम० पैटल शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान और जीवरसायन विभाग के अध्यक्ष तथा निदेशक बल्लभ भाई पटेल वक्ष रोग संस्थान दिल्ली।	दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।	31-5-1975
2. डा० पी० एल० शुक्ल प्रधानाचार्य बी० आर० डी० मेडिकल कालेज गोरखपुर	गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	12-7-1975

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि डा० ए० एम० पैटल उक्त परिषद् के सदस्य बने रहें और भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी 1960 की अधिसूचना संख्या 5-13/59 एम० आई० में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 49 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाव "धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत निर्वाचित" शीर्ष के अधीन निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाए; अर्थात्

"50. 12-7-75 डा० पी० एल० शुक्ल प्रधानाचार्य बी० आर० डी० मेडिकल कालेज गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	11-7-1960 विशालय
---	------------------

[सं० बी० 11013/1/75-एम० पी० टी०]

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING  
(Department of Health)

New Delhi, the 28th November, 1975

S.O. 5328.—Whereas in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1955 (102 of 1955) the following person have been elected by the University specified against each of them to be members

of the Medical Council of India with effect from the date noted against each, namely :—

Name of person	Name of University	Date of election
1	2	3
1. Prof. A.S. Paintal, Head of the Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry and Director, V.P. Chest Institute, Delhi.	University of Delhi	31-5-75
2. Dr. P.L. Shukla, Principal, B.R.D. Medical College, Gorakhpur.	University of Gorakhpur, Gorakhpur, Uttar Pradesh.	12-7-75

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that Prof. A.S. Paintal shall continue to be the member of the said Council and makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 5-13/59-MI dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3" after serial No. 49 and the entry relating thereto, the following serial No. and entry shall be inserted, namely :—

"50. 12-7-75

Dr. P.L. Shukla, Gorakhpur University  
Principal,  
B.R.D. Medical College,  
Gorakhpur (Uttar Pradesh).

[V. 11013/1/75-MPT]

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1975

का० भा० 5329.—यतः दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 (1948 का 18) की धारा 3 के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में पश्चिम बंगाल सरकार ने डा० प्रार० प्रह्लाद, दन्त चिकित्सा कालेज और अस्पताल, कलकत्ता के प्रधानाचार्य डा० प्रसन्त कुमार बसु को 3 जुलाई, 1974 से भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् का सदस्य मनोनीत किया है।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि डा० प्रसन्त कुमार बसु 3 जुलाई, 1974 से आगामी पांच वर्षों के लिए अथवा जब तक उनका उत्तराधिकारी विधिबद्ध मनोनीत नहीं किया जाता, जो भी दीर्घतर हो, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् के सदस्य बने रहेंगे।

[सं० बी० 12013/1/75-एम० पी० टी०]

New Delhi, the 26th November, 1975

S.O. 5329.—Whereas in pursuance of the provisions of clause (c) of section 3 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), Dr. Prasanta Kumar Basu, Principal, Dr. R. Ahmed Dental College and Hospital, Calcutta, has been nominated by the Government of West Bengal to be a member of the Dental Council of India with effect from the 3rd July, 1974;

Now, therefore, in pursuance of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that Dr. Prasanta Kumar Basu shall continue to be a member of the Dental Council of India for a further period of five years with effect from the 3rd July, 1974 or until his successor is duly nominated, whichever is longer.

[No. V. 12013/1/75-MPT]

का० भा० 5330.—यतः दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 (1948 का 18) की धारा 3 के खण्ड (घ) के उपबन्धों के अनुसरण में नखनऊ विश्वविद्यालय की तदर्थ कार्यकारी परिषद् ने के० जी० मेडिकल कालेज,

खननऊ के दन्त कालेज और अस्पताल के प्रोफेसर एवं बिभागध्यक्ष डा० टी० एन० चावला को 29 जनवरी, 1975 से भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् का सदस्य पुनः चुन लिया है।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि डा० टी० एन० चावला 29 जनवरी, 1975 से आगामी पांच वर्षों के लिए अथवा जब तक उनका उत्तराधिकारी विधिबद्ध निर्वाचित नहीं हो जाता, जो भी दीर्घतर हो, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् के सदस्य बने रहेंगे।

[सं० बी० 12013/1/75-एम० पी० टी०]

वि० कृ० अग्निहोत्री, अवर सचिव

S.O. 5330.—Whereas in pursuance of the provisions of clause (d) of section 3 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), Dr. T. N. Chawla, Professor and Head of the Department Dental College and Hospital, K. G. Medical College, Lucknow, has been re-elected by the Ad-hoc Executive Council of the Lucknow University, to be a member of the Dental Council of India with effect from the 29th January, 1975.

Now, therefore, in pursuance of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that Dr. T. N. Chawla shall continue to be a member of the Dental Council of India for a further period of five years with effect from the 29th January, 1975 or until his successor is duly elected, whichever is longer.

[No. V. 12013/1/75-MPT]

V. K. AGNIHOTRI, Under Secy.

(परिवार नियोजन विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1975

का० भा० 5331.—भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (परिवार नियोजन विभाग) की अधिसूचना सं० एक० 1-26/67 स्थापना-1, दिनांक 4 अगस्त, 1971 में प्रकाशित परिवार नियोजन विभाग, प्रधान (जन शिक्षा एवं प्रचार) भर्ती नियमावली, 1971 जिसका संगोष्ठन बाद में परिवार नियोजन विभाग की समसंश्लेषक अधिसूचना, दिनांक 22 अक्टूबर, 1975 द्वारा किया गया था, की अनुसूची के कालम 4 के नीचे प्रविष्टि के स्थान पर 1500-60-1800-100-2000 रु० का संगोष्ठित वेतनमान प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

[सं० 1-26/67/स्थापना-1]

गर्वेश्वर झा, अवर सचिव

(Department of Family Planning)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 5th December, 1975

S.O. 5331.—In the Schedule to the Department of Family Planning, Chief (Mass Education Media) Recruitment Rules, 1971, published vide the Government of India, Ministry of Health and Family Planning (Department of Family Planning) Notification No. F. 1-26/67-Estt. I, dated 4th August, 1971, read with subsequent amendment published vide the Deptt. of Family Planning Notification of even No. dated 22nd October, 1975 for the entry under Column 4 thereof, the revised scale of pay of Rs. 1500-60-1800-100-2000, may please be substituted.

[No. F. 1-26/67-Estt. I.]

SARWESHWAR JHA, Under Secy.

## नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1975

का० आ० 5332:—ऐसा समझा जाता है कि श्री डी० एस० बोस ने, जिसे भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 1322, तारीख 7 अप्रैल, 1967 के अधीन स्थापित कलकत्ता डाक श्रम बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया था, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, 1962 के नियम 4 के उपनियम (5) के खण्ड (v) के अधीन अपना पद रिक्त कर दिया है ;

और उक्त डाक श्रम बोर्ड में एक रिक्ति हो गई है ;

अतः, अब, उक्त नियमों के नियम 4 के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त रिक्ति को अधिशुद्धि करती है।

[सं० एल० डी० सी०/78/75]

क० एल० गुप्त, उप सचिव (एल)

## MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 1st December, 1975

S.O. 5332:—Whereas Shri D. S. Bose who was appointed as a member of the Calcutta Dock Labour Board established under the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1322, dated the 7th April, 1967, is deemed to have vacated his office under Clause (v) of sub-rule (5) of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962;

And whereas, a vacancy has occurred in the said Dock Labour Board;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of rule 4 of the said rules, the Central Government hereby notifies the said vacancy.

[No. LDC/78/75]

K. L. GUPTA, Dy. Secy.

## श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1975

का० आ० 5333:—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 21 दिसम्बर, 1975 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-चार (धारा 44 और 45 के अतिरिक्त ओ पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय-पाँच और छः [धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के अतिरिक्त ओ पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध प्रथम राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

- (1) जिला डिब्रुगढ़ में माकुम मौजा में राजस्व ग्राम संख्या-1 मुकुम पाथर के अन्तर्गत क्षेत्र ;
- (2) जिला डिब्रुगढ़ में माकुम मौजा में मरघेरिता कच्चे के राजस्व ग्राम के अन्तर्गत क्षेत्र।

[संख्या एम-38013/11/74-एच० आई०]

एस० एस० महेश्वरनाथन, उप सचिव

## MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 28th November, 1975

S.O. 5333:—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 21st December, 1975 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act, shall come into force in the following areas in the State of Assam, namely :—

- (1) The area within revenue village No. 1 Makum Pathar in Makum Mauza in Dibrugarh District;
- (2) The area within revenue village of Margherita town in Makum Mauza in Dibrugarh District.

[No. S-38013/11/74-HU]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1975

का० आ० 5334:—यतः केन्द्रीय सरकार ने, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (v) के उपखण्ड (vi) के परन्तुक के उपबंधों के अनुसरण में एक अधिसूचना (भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1836, दिनांक 5 जून, 1975) द्वारा दिल्ली दुग्ध स्कीम के अधीन दुग्ध प्रदाय के लिए उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 22 जून, 1975 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (v) के उपखण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 22 दिसम्बर, 1975 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[का० सं०एस०-11017/9/75-डी आई ए]

New Delhi, the 29th November, 1975

S.O. 5334:—Whereas the Central Government being satisfied that the public interest so required had declared by a notification made in pursuance of the provisions of the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section (2) of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), (being the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1836, dated 5th June, 1975) the industry for the supply of milk under the Delhi Milk Scheme to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from 22nd June, 1975.

And whereas, the Central Government is of the opinion that the public interest requires the extension of the said period by a further period for six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from 22nd December, 1975.

[File No. S-11017/9/75/DIA]

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1975

New Delhi, the 9th December, 1975

का० आ० 5335.—केन्द्रीय सरकार ने, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखण्ड (iv) के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1953 तारीख 6 जून, 1975 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (खख) में यथा परिभाषित बैंकिंग कम्पनी द्वारा चलाए जा रहे बैंकिंग उद्योग को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 29 जून, 1975 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखण्ड (iv) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 29 दिसम्बर, 1975 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[सं० एस०-11025/15/75-डी० के० 1/ए]

New Delhi, the 5th December, 1975

S.O. 5335.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1953 dated the 6th June, 1975, the Banking Industry carried on by a banking company as defined in clause (bb) of section 2 of the said Act, to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 29th June, 1975,

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 29th December, 1975.

[No. S. 11025/15/75/DKI/A]

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर 1975

का० आ० 5336.—यतः केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में यह आवश्यक है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखण्ड (vi) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या आ० आ० 2035 तारीख 18 जून 1975 के द्वारा सिन्धुरिटी वेपर मिल, होशंगाबाद को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 18 जून 1975 से छः मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया गया था ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि लोकहित में उक्त अवधि को छः महीने की और अवधि के लिए बढ़ाना अपेक्षित है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखण्ड (vi) के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एवम् द्वारा उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 18 दिसम्बर 1975 से छः मास की और अवधि के लिए एक लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[सं० एस० 11025/15/75-डी०-1 (ए)]

एल० के० नारायणन्, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

S.O. 5336.—Whereas, the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2035 dated the 18th June 1975, the Security Paper Mill, Hoshangabad, to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 18th June, 1975;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 18th December, 1975.

[No. S. 11025/15/75/DI/A]

L. K. NARAYANAN, Section Officer (Spl.)

New Delhi, the 2nd December, 1975

S.O. 5337.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court No. 3 Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jamadoba Colliery P.O. Jealgora, Distt. Dhanbad of M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on the 24th November, 1975.

#### CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 42 of 1968

Presiding Officer : Shri S. N. Johri, BSc., LL.M.

#### PARTIES :

Employers (Contractor Sri B. B. Das) in relation to the management of Tata Iron & Steel Co. Ltd.'s Jamadoba Colliery, P.O. Jealgora, Distt. Dhanbad.

#### AND

Their workmen

#### APPEARANCES :

For Employers—(1) Sri S. S. Mukherjee, Advocate represented the Tata Iron & Steel Co. Ltd.

(2) Sri D. Narsingh, Advocate represented the Contractor, Sri B. B. Das.

For Workmen—Sri T. P. Choudhury, Advocate represented the workmen.

Industry : Coal.

State : Bihar.

Dhanbad, the 15th November, 1975

#### AWARD

The Government of India in Labour Department made a reference under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 vide its Order No. 2/118/66-LR. II dated 17-9-66 seeking adjudication on the following point :—

“Whether the refusal of the management of Tata Iron & Steel Co. Ltd., Jamadoba, P.O. Jealgora, Distt. Dhanbad and their Contractor Sri B. B. Das to continue the following workers in employment with effect from 30th April, 1966 was justified? If not, to what relief are they entitled? (for names of those 35 workmen refer the schedule attached to this award).”

2. My learned predecessor vide his award dated 25-7-70 held that the workers were the employees of only Sri B. B. Das, Contractor and directed him to pay the retrenchment

compensation. The Contractor filed a writ petition before the Hon'ble High Court at Patna, where in Case No. 2025 of 1970 learned Counsel for the petitioner conceded that the finding of the Tribunal about Sri B. B. Das being the real employer could not be assailed in the writ petition. Having so conceded he raised the dispute about the Contractor's liability to pay retrenchment compensation. On 6-8-73 the Hon'ble High Court set aside the concluding portion of the award relating to the direction for payment of retrenchment compensation by Sri B. B. Das, Contractor on the ground that the Tribunal had not given reasons for jumping to the conclusion that such retrenchment compensation was payable. The case was remanded back for fresh reasoned-out decision on the point whether the Contractor Sri B. B. Das is liable to pay retrenchment compensation to the aforesaid 35 workers. The scope of the present enquiry thus stands very much circumscribed by the remand order. The rest of the findings of my predecessor have been left undisturbed and I have no jurisdiction to revise or review them. Now therefore this Tribunal has to decide:—

"Whether the refusal of Sri B. B. Das, Contractor employer to continue 35 workmen in employment with effect from 30-4-66 was justified? If not, to what relief are they entitled?"

3. The history and the genesis of the dispute may briefly be summarised as follows:

At Jamadoba Colliery, Pits No. 6 & 7 M/s. Tata Iron & Steel Company Limited had employed two Contractors namely Sri B. B. Das and Sri Dirajlal Patel for operating two shifts for feeding the coal to the Power House. The third shift was being departmentally managed by the Company itself through its direct employees. Dirajlal's contract was terminated and his workmen were also employed by Sri B. B. Das, Contractor and he started working in place of Dirajlal as well.

4. Sri B. B. Das, Contractor was not maintaining regular supplies because the workers were not contented. Since 1965 disputes were raised by the Union and complaints were made that the workmen were not being paid full wages and those who were doing trammings work were not being paid Category IV wages. Conciliation proceedings were pending. Sri B. B. Das expressed his inability to pay Category IV wages because the rates, at which he had taken the contract were too poor. He wanted the company to revise the rates of contract in order to enable him to pay proper wages to the workmen. But the company refused to accede to his request. As the correspondence shows the company was on the other hand pressing the contractor at the instance of Asstt. Labour Commissioner to pay Category IV wages to those workers who were doing trammings work. The contractor at first disputed the number of workmen who were engaged in trammings and then admitted before the company that only six of the workmen were so employed. He latter took a somersault to say that no worker was doing any job akin to the job of trammers.

5. During the pendency of the conciliation proceedings, in which both the Company and Contractor were denying that they were the employers and throwing responsibility on each other, police was called on 30-4-66 and these 35 workers were not allowed to work. Neither notice was given nor retrenchment compensation was paid to these workers prior to such termination. Prior permission for the termination of the services of these workmen as envisaged by Section 33 of the Industrial Disputes Act was also not obtained. The workers insisted before the Conciliation Officer that their lot can improve only if contract system was abolished. On the recommendation of the Asstt. Labour Commissioner that the company may abolish the contract system and employ the workers directly, the company terminated the contract of Sri B. B. Das with effect from 17-6-66. But at the same time it refused to accede to the recommendation to provide employment to the aforesaid workers of the Contractor, on the ground that it was not of his headache and responsibility as they were not the employees of the company. All these facts emerged out as undisputed from the pleadings read with proved documents and the record of the conciliation proceedings.

6. It is thus clear that the workers were retrenched on 30-4-66 without notice or payment of retrenchment compensation and in violation of the provisions enacted under Section 33 of the Industrial Disputes Act, while the contract of

Sri B. B. Das was terminated much later i.e. with effect from 17-6-66. According to the statement of Sri Girish Kumar MW-1 (Asstt. Manager of the company) the work in B and C shifts, which was used to be done by these 35 workmen, was from 30-4-66 to 17-6-66 managed by the direct employees of the company. What happened on 30-4-66 and how the affairs were managed thereafter till 17-6-66 will have to be closely scrutinized because that will go a long way in determining the nature and character of the action that was taken against the aforesaid employees.

7. Sri Girish Kumar MW-1 has said that on 30-4-66 when a shift was being worked by the employees of the company, these workers came and started interfering in the work. Police was therefore called to keep them away. He admitted that Police might have come by about 11 A. M. and might have continued till 2 P.M. when the Contractor's shift was to start. He avoided to admit or deny that the workers were stopped from working in the second i.e. B shift. In any case it is obvious that it was the company which did not allow them to work in the second shift which was their working period on 30-4-66. Sri B. B. Das MW-2 has supported this story and has alleged that he never stopped the workmen from working in the shifts. Even Naresh Singh MW-1, the concerned worker, admits that he was discharged by the company. It was the company which had the general supervisory disciplinary powers over the workers of Sri B. B. Das. As such the company and not Sri B. B. Das stopped the workers. The work was actually taken over by the company on that very day though formally the contract of Sri B. B. Das came to be terminated only on 17-6-66.

8. This brings us to the question of volition of the Contractor employer in the matter of refusal to provide them with the work. Analysing the definition of 'retrenchment' as engrafted in Section 2(o) of Industrial Disputes Act Hon'ble Mathew J. (as he then was) observed in C.V.A. Hydross and Sons Vs Joseph Sanjon and others (1967)-ILJ. 509 at page 515 (516 Kerala) that the expression 'termination' by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever appearing in Section 2(o) of the Act, has its own limitations. The limitations are that such termination shall be a termination for a 'reason'. In other words, the words 'termination' and 'reason' imply a certain amount volition and choice and free action on the part of the employer. If volition or free choice is not available by compelling circumstances which leave no option to the employer but to terminate the service, then, the termination is not within the ambit of the connotation of the word 'termination of service for any reason whatsoever'. If the objective situation is such that both 'termination' and 'reason' are beyond the control of the employer, the termination in that context would not be 'retrenchment'. While all retrenchment is termination of service, all termination of service is not retrenchment under Section 2(o) of the Act. Apparently it appears in the present case that neither Sri B. B. Das had the free will nor he terminated the employment. Thus if this objective situation is taken to be real, this termination will not amount to retrenchment. However the unreality of this situation will be apparent from the following discussion:

9. It was pleaded that the company and the contractor had joined hands against the workmen who fell victim of this unholy alliance. There is no direct evidence on this point nor direct or ocular evidence is expected where there is secret conspiracy. Only interpretation of the circumstances and the conduct of the parties can tell the truth lying latent behind the apparent story.

10 The correspondence between the contractor and the company indicates that the company was dissatisfied with the working of the contractor and was reluctant to accede to his demand to revise the rates of contract while the contractor was pressing for the same in order to enable him to pay proper wages to the workmen. This difference between the two was only superficial. On the representations made by the union the company was being pressed by the Asstt. Labour Commissioner to abolish the contract system since the contractor was regularly flouting the Labour laws and was not paying proper wages. Asstt. Labour Commissioner was further advising the company to withhold the bills of the contractor and pay from such bills the amount of the difference of wages to the workmen (see Ext. M-7). The company was in its turn writing letters to Sri B. B. Das to pay proper wages else it shall withhold his payments. Or the other hand there was regular short loading of coal from 23-4-66 onwards vide Pxt. M-13 and the contractor

was saying that he had lost all control on the workers. The company was thus finding it difficult to continue with the contractor. Pressure of the workers through Asstt. Labour Commissioner associated with this continued short loading etc. had brought out a situation in which the company had no alternative but to terminate the contract.

11. On the other hand the situation had so turned against the financial interest of the contractor that he wanted a safer exit without hanging liabilities of payment of retrenchment compensation etc. He could not himself terminate the services of the workers without exposing himself to such liabilities. The company was in a safer position. It came to the rescue of the contractor by itself refusing them permission to work under the pretended exercise of supervisory and disciplinary power, because it could still say that it was not the employer of those workmen and was therefore not responsible for the consequences of such termination. This brought them to a meeting point in mutual interest and collusion appears to have followed resulting in the termination of the services of these workers by the company, while Sri B. B. Das preferred to remain a silent spectator.

12. All the correspondence pursued in the circumstances mentioned above indicates that the company and the contractor were entering into correspondence with each other only on account of the pressure of the Asstt. Labour Commissioner about the ways and means for raising the wages of the workmen. Still the net result was that the workmen were not getting adequate payments. Contractor was pressing the company for the revision of his low rates of contract and the company was tight on the settled terms. Neither the company for the revision of his low rates of contract in the net result the workers were the real sufferers. I am thus not inclined to attach much importance to these superficial differences exhibited by the correspondence between the company and the contractor.

13. As discussed above it appears that the contractor was fed up with the complaints and agitations of the workers and wanted to extricate himself from the situation. He had already victimized 11 workers. He did not want to pay them adequately so as to minimise his profits. The company was also exasperated with this labour trouble which was assuming bigger and bigger dimensions since 1965 (see correspondence proved in the case). All this resulted in short supply of coal and consequent difficulty in running the Power House. The labour was already pressing the company through Asstt. Labour Commissioner to terminate the contract. It was in these circumstances that the contractor had, if not, tacitly, consented rather impliedly to the termination of the employment of these workers by the company.

14. In fact Sri B. B. Das, Contractor raised a dispute only in the name's sake that he was not the employer of these workmen because in his letter dated 25-4-66 Ext. M-11 he had already categorically admitted that these workers were his employees and not the employees of the company.

15. It was against his previous stand taken in the written statement that the contractor in the witness box tried to blindly support the plea of the company raised about the interference of the workmen of the contractor in the working of the direct employees of the company even before the B shift started. No message given to the Police or memo sent to it has been produced or proved in support of the statement that the trouble started in A shift and police appeared much before the starting of contractors' shift. Record of the Police Station has not been summoned to prove the timings of the movements of the Police on that day for proving the real nature of the incident. Non-production of such papers may in the present circumstances give rise to adverse inference so far as this plea is concerned. Except the Asstt. Manager of the company and the interested contractor Sri B. B. Das, who had deposed against his own written statement, no one has come forward to say about such interference by the workers of the company.

16. The contractor had pleaded in para 17 of the written statement that:—

"the company, however blamed Sri B. B. Das for the alleged lack of his control over the workmen and itself stopped their work from the second shift of 30-4-66 when it found that their discontentment was

on increase and with the help of Police drove them out."

Thus according to this written statement the workers of the contractor did not interfere in the working of the direct employees of the company before the start of the second shift. Police was called only when the second shift started and the workers were not allowed to work in the second shift. All this story changed when Sri B. B. Das appeared in the witness box and forgetting what he had written in his written statement he started fully endorsing the version of interference as propounded by the company. This exposes his reckless indifference to truthfulness and indicates his conduct that he is out to support the company even at the cost of his integrity.

17. Moreover what could be the earthly reason, for the workers of the contractor to interfere in the working of the direct employees of the company when even their shift had not started? There is no allegation that the Union had given any notice or call for strike nor it is alleged that the workers of the contractor resorted to strike and therefore wanted the direct employees of the company to join them. In the absence of any reason behind such alleged interference the story hardly inspires conviction and the fact remains that without there being any such unlawful activity on the part of the workers the company forcibly stopped them from working and drove them out.

18. Normally the company, if it was so irrevocably dissatisfied with the Contractor's allegedly incorrigible workers, should have first terminated the contract or should have asked the contractor to oust the unwilling workers or punish them for misconduct and recruit those who were willing to perform the job labouriously and efficiently. Atleast either the taking over and the termination of the contract should have been simultaneous or in quick succession. Long gap of more than 1-1/2 months between forcible taking over of the work, which should have normally succeeded the termination of contract and the real termination of the same on 17-6-66, do clearly indicate that the real motive was to oust the workers in collusion with the contractor. The company tried to save the contractor till ultimately under the pressure of Asstt. Labour Commissioner it was compelled to do away with the contract system.

19. Normally for this additional work taken over by the company from the Contractor Sri B. B. Das, the company must have employed some more workers to do the job. Social conscience and moral obligations arising out of the ethics of employment should have dictated the company to have, in the matter of fresh recruitment, given first preference to these workers of the contractor who were being thrown out of employment on account of the termination of the contract vide Section 25 of Industrial Disputes Act. The workers of more than one years' standing should have in the normal course gone with the work, as is generally contemplated by Section 25FF of Industrial Disputes Act in case of a change in the employer. The fact that the company terminated the contract but refused to accede to the recommendations of the Asstt. Labour Commissioner to take over any of the workmen of the contractor as its direct employee, is clearly indicative of company's real annoyance against the workers. The contractor was already annoyed with them because of long pending agitations and also because it was only on account of them that he was exposed to the situation of termination of the contract. Hence it could safely be presumed that both of them joined hands against the common enemy.

20. If as expressed in the company's letter to the contractor, the company really felt concerned about the fact that the workers were dissatisfied and were not co-operating with the contractor because of substandard payment of wages by him and accepted the proposal of the Asstt. Labour Commissioner to arrange for some relief to these suffering workers on that account by withholding bills, then there should have been no hitch in taking over the suffering workmen under its direct management after paying them standardised wages. But the letter appears to be shedding only the crocodile tears under the pressure of Asstt. Labour Commissioner which is obvious from the fact that the company did not provide them with any relief. This shows that under the pressure of the Asstt. Labour Commissioner it wanted to show lip-sympathy with the labourers but deeper and ulterior motive governed the action. It is not alleged that the workers were lazy or cannot give proper output hence the company could not take



them over. In fact the company has given no reason as why it did not want to provide employment to these suffering workmen. All this shows that the correspondence between the company and the contractor is only a superficial covering over the simulated conflict of interest between them for hiding the deeper and real collusive intention and scheme to oust the agitating workers of the contractor.

21. It is true that there is evidence that the company had disciplinary powers over the workmen of the contractor but that power did not make them the employers and the termination of the services or permanent refusal to provide them with the work could be done only by the employer and not by the company under the garb of the exercise of these disciplinary powers and that too without notice or payment of retrenchment compensation and in breach of the provision enacted by Section 33 of the Industrial Disputes Act because conciliation proceedings were pending at that time. The company had no right to oust the workers during the subsistence of the contract. Such action could be taken only by the contractor. But the contractor did not insist upon his right and allowed the company to act arbitrarily and exercise these powers which only the contractor was competent to exercise. It was his duty to interfere and assert that his contract was subsisting and he would manage the affairs in his own way. This situation gives rise to the concept of agency and it can well be presumed that the company in ousting the workers of the contractor acted merely as the implied agent of the contractor. Silence of the contractor amounted to consent because there was duty to speak and resist the action of the company and the continued long silence of the contractor for 1 1/2 months i.e. till the actual termination of the contract, amounted to virtual ratification of the action so taken by the agent, company. In this way in effect it will be presumed that the contractor himself ousted the workers through the agency of the company, himself remaining behind the screen. It was an intelligent device which appeared to exonerate both of them from any liability—the company on the ground of not being the employer and the contractor on the ground of not apparently being instrumental in terminating the employment. This ouster by the contractor amounted to retrenchment because it will be deemed that the termination was with the volitional consent of the contractor or rather under a device invented by him to oust the workmen through the instrumentality of the company with the object of saving himself from the liabilities arising out of such action. Obviously such retrenchment was unjustified and illegal for want of notice, want of prior payment of retrenchment compensation in lieu thereof and want of compliance of Section 33 of the Industrial Disputes Act because conciliation proceedings were still pending.

22. In *Assam Oil Company Vs. its workers* 1967-I.L.L.J. 587(591) the Supreme Court observed that—

"we are not prepared to accede to the argument urged before us by the learned Additional Solicitor General that whenever, the employer purports to terminate the services of his employee by virtue of the power conferred on him by the terms of the contract, the Industrial Tribunal cannot question its validity propriety or legality . . . exercise of the power in question to be valid should always to be bonafide. If the bonafides of the said exercise of power are successfully challenged, then the Industrial Tribunal would be entitled to interfere with the order in question. It is in this context that Industrial Tribunal must consider whether the discharge is mala-fide or whether it amounts to victimization or unfair labour practice or is so capricious for any reason as would lead to the interference that it has been for ulterior motives and not in bonafide exercise of the power conferred by the contract."

23. More recently the same Court observed in *L. Michel and another Vs. Mr. Jonson Bumps India Limited* 1975—I.L.L.J. 262 in still stronger and unmistakable terms that, to hit below the belt is not the industrial law. One of the vital factors which must inform the understanding and application of industrial jurisprudence is constitutional mandate of Part IV obligating the State to make provision for securing just and human conditions of work. Security of employment is the first requisite of workers' life. Labour Court has to judge by the social conscience and the judicial construction of the law in this branch of discharge versus disguised dismissal. Colourable exercise of the powers vitiates bonafides and the Tribunal is competent to tear out the veil in order to peep into the

reality behind an otherwise innocuous looking order manoeuvred to have been passed through an unauthorised agency with the object of protecting the real employer from the liabilities arising out of such highhanded action. In the present case the workers were so discharged on account of their union activity and such a discharge has been held to be mala-fide by the Supreme Court in the aforesaid case of *Assam Oil Company*, whatever might be the form or device

24. In *Subodh Kumar Chatterjee Vs. District Signal Tele-Communication Engineer* 1970—II L.L.J. 179 Patna High Court held that retrenchment without paying retrenchment compensation was illegal and according to the Supreme Court as held in *National Iron & Steel Company Vs. State of West Bengal* 1967—II L.L. 23 payment of retrenchment compensation is a condition precedent for its validity and operativeness. In the absence of such payment in the present case the retrenchment so devised was illegal and unjustified.

25. The argument that when the workers demanded reinstatement, they cannot be given retrenchment compensation in lieu thereof, has no force. Firstly there is nothing to show that they wanted reinstatement in the employment of Sri B. B. Das whose employees they have now been held. In fact they were pressing that claim against the company or in other words they simply wanted the company to provide direct employment to them instead of leaving them to the mercy of the contractor. If, as has been held, the company is under no legal obligation to employ them and the contract industry has ceased to exist due to the termination of the contract, there can be no order of reinstatement. In *Chembur Co-operative Industrial Estate Limited Vs. N. K. Chhatra* A.I.R. 1975, Supreme Court 1725 it was held that in suitable cases the Tribunal can exercise the discretion to grant only retrenchment compensation where reinstatement is prayed for. The order of reference has given a wide scope to this Tribunal in the matter of recommending nature of relief against this unjustified action of the employer.

26. Thus even after reconsideration of the matter, as directed by the High Court, in the light of the above discussion, the workers are held to be entitled to retrenchment compensation from Sri B.B. Das, Contractor employer under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947 because the cause of action arose when the contract industry was a living industry. Award is given accordingly.

S.N. JOHRI, Presiding Officer.  
Central Govt. Industrial Tribunal  
Cum-Labour Court (No. 3-  
DHANBAD).

#### SCHEDULE

1	2
1. Sri Nareish Singh	Coal Supply Mazdoor
2. Sri Fuleswar Singh	"
3. Sri Ganga Singh	"
4. Sri Kara Bhuia	"
5. Sri Biswanath Singh	"
6. Sri Lakhan Singh	"
7. Sri Yakun	"
8. Sri Sosti Gorai	"
9. Sri Sitaram Singh	"
10. Sri Sitaram Mali	"
11. Sri Rameshwar Singh	"
12. Sri Sarjoo	"
13. Sri Sudhir Gorai	"
14. Sri Rajendra Singh I	"
15. Sri Rameshwar Singh	"
16. Sri Akleswar Singh	"
17. Sri Dato Ram	"
18. Sri Liloo Singh	"
19. Sri Kamleshwari	"
20. Sri Gobind Singh	"
21. Sri Jamun Singh	"
22. Sri Benarashi Singh	"
23. Sri Gokul Mali	"

## SCHEDULE

1	2
24. Sri Arjun Singh	Coal Supply Mazdoor
25. Sri Anuplall Singh	"
26. Sri Nabin Mandal	"
27. Sri Biroo Mahato	"
28. Sri Kishun Singh	"
29. Sri Karoo Singh	"
30. Sri Baldeo Saw	"
31. Sri Jaldhar Singh	"
32. Sri Rajendra Singh II	"
33. Sri Dinesh Singh	"
34. Sri Bihari Mali	"
35. Sri Akhil Singh	"

The award is submitted to the Central Govt. in Labour Department as required by Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

[No. 2/118/66-LR—II]

S. N. JOHRI, Presiding Officer.

New Delhi, the 20th December, 1975

**S.O. 5338.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 2 Dhanbad) in the Industrial dispute between the employers in relation to the Jamadoba Colliery of Messrs. Tata Iron & Steel Co., Ltd., P. O. Jealgora Distt. Dhanbad and their workmen which was received by the Central Government on the 24-11-75.

## (AWARD)

## BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL

## TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

## PRESENT :

Shri K. K. Sarkar, Judge, Presiding Officer.  
Reference No. 13 of 1975

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

## PARTIES :

Employers in relation to the management of Jamadoba Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Post Office Jealgora, District Dhanbad,

## AND

Their workmen.

## APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

On behalf of the workmen—Shri P. K. Bose, Advocate.  
State : Bihar.

Dhanbad, 20th November, 1975.

## AWARD

The Government of India, Ministry of Labour being of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Jamadoba Colliery of Messrs Tata Iron & Steel Company Limited, Post Office Jealgora, District Dhanbad and their workmen, by Order No. L-20012/183/74-LRII dated 11th February, 1975 referred the same to this Tribunal under S. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act for adjudication upon the issue as in the schedule below :

"Whether the action of the management of Jamadoba colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Post Office Jealgora, District Dhanbad, in terminating the lien of Shri Radha Singh, Piece Rated Hammerman in his permanent appointment and placing him in the 'Badli' list, vide their letter No. JMA/104/2776/70 dated 3/5-6-70, was justified? If not, to what relief is the workman entitled and from what date?"

Briefly stated, the case of the workmen is that the concerned workman Shri Radha Singh was a piece rated hammerman in Jamadoba Colliery w.e.f. 1-7-1954. He went home on sanctioned leave for 28 days i.e. from 13-12-69 to 8-1-70. While at home he was falsely implicated in a murder case and taken into police custody. Accordingly he sent a petition from jail praying for an extension of leave by 56 days. As he was not released on the expiry of 56 days, he sent another application praying for extension of leave till he was released. The concerned workman did not get any communication from the management in reply to his petitions. He therefore presumed that his prayer for extension of his leave till release had been granted. On 12-8-73 he was released from jail on bail and he came to Jamadoba colliery and prayed for resumption of duty. His prayer was turned down and he was intimated that his name has been struck off from the rolls. The concerned workman approached the Group Joint Grievance Committee functioning in the colliery but failed to get justice from them. The action of the management in placing him in the 'badli' list is alleged to be unjustified and illegal and reinstatement in job with full back wages in prayed for.

The case of the management in short is that the concerned workman did not report for duty on the expiry of his leave for 28 days which ended on 8th January, 1970. He sent an application from Sub-jail, Banka for extension of leave for 56 days with effect from 9-1-1970. The management by their letter dated 9-4-70 sent under registered post A/D informed the concerned workman to his jail address that the leave was not granted and he was asked to report for duty at once. He did not do so but another letter dated 6-2-1970 was received on 8-2-70 asking for 28 days leave w.e.f. 9-2-70. The management by letter dated 3/5-6-70 informed him that he has lost his lien on his appointment and he has been kept on 'badli' list. They deny that the concerned workman made any application for extension of leave after expiry of 56 days. The concerned workman came to the colliery on 20-8-73 i.e. about 3 years after termination of his lien on appointment. The Group Grievance Committee unanimously decided that there was no merit in his case and according to the procedure laid down there was no scope to refer the matter to the Central Grievance Committee.

Admittedly the sanctioned leave of the concerned workman expired on 8-1-70. The point taken by the workmen is that the concerned workman applied from the Sub-jail for extension of his leave twice, i.e. first for 56 days and then till his release from the jail and as the management failed to reply to his applications for extension of his leave, the extensions of leave as applied for should be deemed to have been granted. I have to consider the workmen's case about the application for extension of leave on facts and evidence. The management admits receipt of application for extension of leave for 56 days from the Banka sub-jail on 17-1-70 and another application dated 6-2-70 for extension of leave by 28 days. According to the management they had sent a letter dated 9/10-4-70 under registered post A/D to the concerned workman to his jail address refusing extension of leave but the said letter came back undelivered with the postal remark 'no such man in jail'. Papers have been filed in respect of the same. The above cannot be deemed to be a service of the letter refusing the leave on the concerned workman. Accordingly I may take it that the extension of leave for 56 days and for 28 days should be deemed to have been granted to the concerned workman. The question does not end there. The fact remains—what next? The management does not admit receipt of the concerned workman's letter for extension of leave till his release. As this matter is a disputed one it is for the workmen to prove about the issue and service of the last alleged letter of the concerned workman for extension

of his leave till release from jail. What is the evidence adduced in this respect? The evidence of MW. 1 S. K. Sharma who is a clerk in the personnel department of Jamadoba colliery is that no letter for extension of leave was received from the concerned workman after receipt of Ex. M 1 which is a letter dated 6-2-70 from Banka sub-jail forwarded by the Jailor. The concerned workman was examined as WW. 1 and in his chief he says that after expiry of his leave for 28 days he could not return back being arrested by the police and he stated the above facts in a letter sent to the management to which he did not get any reply. He does not say that he had sent any letter for extension of his leave till release. Again in his cross-examination the concerned workman says that from the jail he had sent two letters to the management for extension of his leave and that the second letter of extension was dated 6-2-70 by 28 days. The evidence of the concerned workman as discussed above does not reveal that he had sent any letter to the management for extension of leave till his release. There is also no paper or independent evidence forthcoming in this matter. In view of the above I think that I shall not be wrong in holding that the concerned workman did not apply for extension of leave till his release, and I so hold. The matter therefore boils down to this that after expiry of his sanctioned leave on 8-1-70 his prayer for extension of leave for 28 days and/or 56 days should be deemed to have been granted in the circumstances as discussed by me above. The period of his absence thereafter till he was released from jail and came back to resume his duties, i.e. a period of about 3 years goes unaccounted. In other words, there was no sanction of leave by the management on any application by the concerned workman. The learned Advocate representing the workmen submits that the concerned workman was in jail custody and he has given satisfactory explanation about his absence from duty. In the present case the Reference had proceeded on the footing that the management had terminated Radha Singh's lien and had placed him in the badli list, presumably in view of the standing order No. 9, copy of which has been placed before me and the order of Reference is whether the action of the management in this respect is justified. The question therefore arises whether the management had acted rightly under the Standing Orders or whether the action of the management is illegal, mala fide and all that. If it be held that Standing Order No. 9 is not applicable in this case it will really amount to holding that the entire foundation of the dispute between the parties as mentioned in the order of Reference was non-existent. Standing Order No. 9 says that if an employee remains absent beyond the period of leave originally granted or subsequently extended he shall lose his lien on his appointment unless (i) he returns within 8 days of the expiry of the leave and (ii) gives an explanation to the satisfaction of the manager of his inability to return before the expiry of the leave. In case the employee loses his lien on the appointment he shall be entitled to be ket on the badli list. The proved facts as discussed by me earlier are that after the expiry of his sanctioned leave upto 8-1-70, the concerned workman will be deemed to have been granted extension of leave for 56 days and/or 28 days as applied for by him from the sub-jail. The proved fact as discussed by me above further remains that after expiry of his extension of leave for 28 days and/or 56 days, the concerned workman did not apply for extension of leave till his release and no such letter for further extension was received by the management. So it comes to this that the concerned workman has to return within 8 days of the expiry of the leave for 28 days and/or 56 days and to give an explanation to the satisfaction of the manager of his inability to return before the expiry of the above leave. In this case on proved facts as discussed by me earlier the concerned workman did not return within 8 days of the expiry of his leave for 28 days and/or 56 days and give an explanation for his non-return. In that view of the matter the concerned workman having absented beyond the period of leave originally sanctioned or subsequently extended he shall lose his lien on his appointment. In this connection I may mention that clause (i) and clause (ii) of Standing Order No. 9 are conjunctive and not disjunctive. In other words, clause (i) & clause (ii) are joint requirements and not separate and distinct requirements. The matter will be simpler to understand if we take into consideration the word 'and' after clause (i). If the word was 'or' instead of 'and' in between clause (i) and (ii) the matter would have been that the two requirements are independent of each other. That is not so in this case. This question arose in a case between management of Messrs. Shiva Flour Mills, Bhagalpur-v-the workmen and the Hon'ble Patna High Court in the case reported in 1970 Lab. I. C 1006 held as follows: ..... 'An

argument was advanced in other cases decided by this Court as also before another bench that the word 'and' occurring in clause 9 of the standing orders should be read as 'or' but such an argument has been consistently rejected'. The Patna High Court further held that the termination of lien of the employee on his appointment is automatic on the expiry of his leave and the period of 8 days within which under clause 9 of the standing order he is required to return and explain to the management his inability to return before the expiry of the leave. This goes to show conclusively that standing order No. 9, clause (i) and (ii) are conjunctive and not disjunctive. The learned Advocate representing the workmen submits that according to standing order No. 9, clause (ii) the concerned workman has given satisfactory explanation for his non-return after expiry of his leave. As I have already stated that giving explanation for non-return after expiry of leave is not by itself sufficient being not independent. He has to return within 8 days of the expiry of his leave and to explain to the satisfaction of the management about his inability to return on the expiry of his leave. This has not been done in the present case. Accordingly the requirements of Standing Order No. 9 has not been fulfilled by the concerned workman and so he is not entitled to the protection provided by the said standing order. I may look at the point from another angle. The case of the workmen is that the concerned workman could not return to duty for no fault of his and so his lien cannot be terminated and he should be granted leave. The question therefore arises whether the management was obliged to regularise his absence for about three years by grant of leave for the period. The concerned workman therefore seeks to get relief as to leave for an unspecified and indefinite period which amounted to about 3 years. The workmen have failed to show any rule by which the management is obliged to grant leave for indefinite period which amounts to 3 years in such circumstances. There must be some basis either as a matter of rule or as a matter of practice regarding grant of leave for 3 years at a stretch and there is none before me placed from the side of the workmen. Admittedly the workman availed the opportunity of his case being reviewed by the Group Joint Grievance Committee composed of representatives of the management and the workmen and admittedly the said Committee after discussions rejected the case of the concerned workman as being without merit. The management by their letter marked Ext. W. 9 explained the procedure about the consideration of a matter by the Group Joint Grievance Committee and Central Joint Grievance Committee. It is given out by them that in those cases where the Group Joint Grievance Committee could not arrive at unanimous decision or where the management or the recognised union objects to the unanimous decision, they shall be forwarded to the Central Joint Grievance Committee within 7 working days of the date on which the Group Joint Grievance Committee arrived at a final decision. Thereafter the Central Joint Grievance Committee will give its decision. The above procedure does not appear to have been challenged by the workmen. It appears from Ext. W. 3 that the decision of the Group Joint Grievance Committee was unanimous and there is nothing to show that the recognised union objected to the said unanimous decision within the time as mentioned above. Be that as it may the matter is at large before this Tribunal for its decision. The management has filed a badli register (Ext. W. 18) in which the name of Radha Singh has been shown as placed on badli list from 2-6-70 Ext. W. 2 shows that the concerned workman was informed that his name has been struck off from the company's rolls. Ext. M 2 bears an endorsement by the management that the name of the concerned workman was put in badli list from 2-6-70 for his over stayal of his leave. The case of the management is that the post could not be kept vacant for an indefinite period. The case of the management gets support from the case between Indian Iron & Steel Co.—v—their workmen as reported in 2 S.C.L.J 1023 where it is stated that it is true that the arrested men were not in a position to come to their work because of their arrest by the police. This may be unfortunate for them but it will be unjust to hold that in such circumstances the company must always give leave even when an application for leave is made. I have discussed above the industrial dispute in question from all conceivable angles, the main of which is on the basis of Standing Order No. 9 and the order of Reference. Much though I may have sympathy for the concerned workman his case does not stand on merit or fact. I do not find the action of the management unfair, illegal or unjustified.

In the result, the action of the management of Jamadoba colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Post

Office Jealgora, District Dhanbad in terminating the lien of Shri Radha Singh, Piece Rated Hammerman in his permanent appointment and placing him the 'Badli' list is justified. The workman is entitled to no relief.

This is my award.

[No. L-20012/183/74-LRII]

K. K. SARKAR, Presiding Officer.

**S.O. 5339.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, No. 3 Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management (Managing Contractor Shri Chandanmal Jain of Golden Sinidih Colliery, P.O. Tundoo, Dist. Dhanbad) and their workmen which were received by the Central Government on the 22nd November, 1975.

**CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-  
CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD**

Reference No. 78 of 1968

Presiding Officer : Shri S. N. Johri, B.Ss., LL.M.

Employers (Sri Chandanmal Jain, Managing Contractor) in relation to Golden Sinidih Colliery, P.O. Tundoo, Dist. Dhanbad.

AND

Their workmen represented by Khan Mazdoor Congress, P.O. Jharia, Dist. Dhanbad.

**APPEARANCES :**

For Employers—(1) Sri S. S. Mukherjee, Advocate represented the Bharat Coking Coal Ltd. (2) Sri G. Prasad, Advocate represented the old management of Golden Sinidih Colliery.

For Workman—Shri G. C. Munshi, President Khan Mazdoor Congress.

Industry : Coal.

State : Bihar.

Dhanbad, the 15th November, 1975

**AWARD**

Government of India in the Ministry of Labour made a reference vide its Order No. 2/1/67-LR. II dated the 3rd February, 1967 on the question—

"1. (a) Whether Shri Chandanmal Jain, Managing Contractor at Golden Sinidih Colliery, P.O. Tundoo, Dist. Dhanbad was justified in refusing employment to the workmen detailed below (names mentioned in Schedule A to this award) with effect from 10th November, 1966 ?

(b) If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?

2. (a) Whether Shri Chandanmal Jain, Managing Contractor at Golden Sinidih Colliery, P.O. Tundoo, Dist. Dhanbad was justified in refusing employment to Shri Ramjan Mian, Railing Mazdoor, from 10th November, 1966 to 1st December, 1966 ?

(b) If not, to what relief is the workmen entitled ?"

2. An award in the case was given by my learned predecessor Sri Sachidanand Sinha on 21-8-69. However the award was challenged before the Hon'ble High Court of Patna in writ petition No. 1513 of 1969 by the Managing Contractor of Golden Sinidih Colliery. Vide Order dated 1-9-71 the Hon'ble High Court held that question No. 2 is finally decided by the award and remanded the case to again to prepare fresh answer to question No. 1 on the evidence already recorded. The award in respect of question No. 1 was thus set aside. Some papers of settlement were also produced before the Hon'ble High Court which ordered that the papers be produced before the Tribunal and the workmen be also allowed to place such material before it

in connection of those papers as they may be advised to do. There was a direction that the Tribunal may then examine as to the effect of these papers on the reference in question in regard to question No. 1. After this remand Bharat Coking Coal Limited was impleaded as a party to the case because it had taken over the management and it filed a reply.

3. The Union which agitated the industrial dispute entered into a compromise settlement with the old management as well as with the new management i.e. Bharat Coking Coal Ltd. According to the terms of settlement Bharat Coking Coal Limited has agreed to reinstate 20 of the workmen with continuity of the service within 15 days of their reporting for duty but without any liability to pay the back wages. The Union gave up the claim of reinstatement and back wages of all other workmen involved in the dispute. Similarly there was an agreement with the erstwhile employer that the union, in view of the reinstatement of 20 workmen by the Bharat Coking Coal Limited, gives up the claim in toto against the erstwhile employer.

4. A question was raised whether such a settlement with respect to only some of the workmen and not with respect to all of them could be honoured and recorded by this Tribunal. This is a dispute raised by the union and not by the individual worker. As per Rule 37 of the Industrial Disputes Rules (Central) the acts of the union are binding on the worker represented by it. It is not disputed that the union has a right to give up the claim with respect to some of the workmen. In the case of Eastern Manganese and Mineral Ltd. Vs. Industrial Tribunal (Central) Dhanbad, it was held by Patna High Court in 1968 L.I.C. 1430 at page 1432 with reference to the Supreme Court view expressed in State of Bihar Vs. D. N. Ganguly A.I.R. 1958 Supreme Court 1018 that once a settlement is filed the Tribunal has to immediately agree to make an award in terms of settlement between the parties unless it is challenged on the ground of fraud, misrepresentation or undue influence.

5. I enquired from the Labour Union Leader Shri G. C. Munshi whether he is the signatory and he has agreed to the settlement to which he replied in affirmative. I further asked whether he wants to file any petition challenging the settlement on the ground of fraud, misrepresentation or undue influence but he said that he did not want to do so.

6. The settlement is therefore recorded and the award is passed in terms of settlement between the parties. The question No. 1 is answered accordingly. Twenty of the workmen as per list given in the schedule No. 2 attached to this award are entitled to reinstatement by the present management Bharat Coking Coal Limited if they report for duty within 15 days of the date of recording the settlement i.e. before 30th of November, 1975. The union has given up the claim with respect to others. None of the workmen so reinstated will be entitled to back wages, dearness allowance, quarterly bonus, annual bonus or leave wages from 10th November, 1966 to the date of the resumption of their duty under Bharat Coking Coal Limited. The workers or the union are not entitled to press any claim against the erstwhile management.

S. N. JOHRI, Presiding Officer.

**SCHEDULE 'A'**

1. Jyoti Rewani	Fitter Mistry
2. Onkar Yadav	Guard.
3. Nathu Mahato	Trolley man.
4. Govind Mahato	"
5. Nukal Mahato	"
6. Somar Mahato	"
7. Hari Kumhar	"
8. Nandoo Mahato	"
9. Sukar Mahato	"
10. Guhi Majhi	Miner
11. Kalicharan Majhi	"
12. Sahdeo Manjhi	"
13. Ludhuoo Manjhi	"
14. Ramdhan Majhi	"
15. Rasik Majhi	"

16. Chhotan Majhi	Miner
17. Bahadur Majhi	"
18. Churka Majhi	"
19. Ritbaran Majhi	"
20. Jageswar Bhuia	"

The award is submitted to the Central Govt. in Labour Department as required by Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

[No. 2/1/67/LR II]

S. N. JOHRI, Presiding Officer.

T. S. KRISHNAMURTHI, Under Secy.

New Delhi, the 5th December, 1975

**S.O. 5340.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Calcutta, in the matter of an application under section 33-A of the Industrial Disputes Act, 1947 from Shri Dilip Kumar Mukherjee, which was received by the Central Government on the 4th December, 1975.

#### CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Misc. Application No. 10 of 1975

#### PRESENT:

Justice E. K. MOIDU—Presiding Officer.

#### PARTIES:

Shri Dilip Kumar Mukherjee, 77/9A, Badrahipur Road,  
Calcutta-32.—Applicant.

Vs.

Armen George & Co. (Private) Ltd., 35, Ezra Street,  
Calcutta.—Opp. Party.

#### APPEARANCE:

On behalf of Applicant—Shri Hiralal Roy, Advocate.

On behalf of Opp. Party.—Sri Biswanath Ash, Advocate.

State: West Bengal

Industry: Port & Dock

#### AWARD

This is an Application under Section 33-A of the Industrial Disputes Act, 1947, arising out of Reference No. 11 of 1975 (already disposed of), by one Sri Dilip Kumar Mukherjee, an employee of Messrs Armen George & Co. (Private) Ltd., against the employer alleging that the said Company was guilty of contravention of Section 33 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and praying for redressal of his grievances.

2. This application was taken up for hearing out of turn at the request of the parties who requested that an award should be passed in terms of the compromise arrived at on 13-11-1975, a copy of which was filed before the Tribunal. I find the compromise is fair and reasonable and as such an award is passed in terms of the compromise. The compromise will form part of the award.

E. K. MOIDU, Presiding Officer.

Dated, Calcutta,  
the 24th November, 1975

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Misc. Application No. 10 of 1975

(U/s. 33-A of the I.D. Act, 1947)

(Arising out of Reference No. 11 of 1975)

Dilip Kumar Mukherjee, 77/9A, Badrahipur Road,  
Calcutta-32.—Complainant.

Versus

Armen George & Co. (Private) Ltd., 35, Ezra Street,  
Calcutta-1.—Opposite Party.

The humble joint petition of the parties above-named,  
Most respectfully Sheweth :

1. That the above matter is pending before this Hon'ble Tribunal.

2. That the parties have arrived at an amicable settlement of the matter, out of the Tribunal, on the following terms, namely :—

(1) That Sri Dilip Kumar Mukherjee, the Complainant, has accepted termination of his services under the Opposite Party Company, with effect from 1st April, 1975, and he does not claim reinstatement, re-employment and/or further employment under the Opposite Party.

(2) That at the earliest request of the complainant that the termination of his services, effective from 1st April, 1975, be treated as by discharge, instead of by dismissal, the opposite party, without prejudice to its contentions, and as a gesture of goodwill on its part, without creating hereby any precedent for the future, and as a very special case, has agreed to treat the termination of the services of the complainant, with effect from 1st April, 1975, as a case of discharge, and to pay him full benefits up-to-date.

(3) That accordingly, the Opposite Party Company has paid the complainant today the sum of Rs. 4,500 (Rupees four thousand five hundred only), and the complainant has accepted the said amount, in full and final settlement of all his legal entitlements, including Retrenchment Compensation, Gratuity, Bonus and other legal dues, up-to-date, and has acknowledge receipt of the aforesaid amount, by a stamped Receipt therefor, as well as by putting his signature in all relevant Registers and Vouchers of the Opposite Party, in token of receipt of the amounts under different heads of his legal entitlements, on acceptance of termination of his services under the Opposite Party, effective from 1st April, 1975.

3. That in the above circumstances, the Complainant does not want to pursue the Complaint any further..

The parties accordingly humbly pray that your Lordship would be graciously pleased to dispose of the Complaint as not pressed, and make an Award, incorporating therein the terms of the settlement.

And, for this act of kindness, as in duty bound, the petitioners shall ever pray.

[No. L-32014(1)/75-D. IV(A)]

13th November, 1975.

NAND LAL, Section Officer (Spl.)

**S.O. 5341.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Kanpur in the industrial dispute between the employers in relation to the Punjab National Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 2nd December, 1975.

#### BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (III) U.P.

AT KANPUR

#### PRESENT:

Shri K. N. Srivastava—Presiding Officer.

Adj. Case No. 1 of 1975 (Central)

In the matter of an industrial dispute between the concern known as M/s. Punjab National Bank, Nayaganj Branch, Kanpur.

Versus

Their workman through U.P. Bank Workers Organisation,  
2, Navin Market, Kanpur.

## APPEARANCES:

For the employers : Sri G. B. Singh, Authorised Representative.

For the workman: Sri P. N. Sachin, Workman concerned.

INDUSTRY : Banking

DISTRICT : Kanpur  
(Kanpur Region)

Dated : November 26, 1975.

## AWARD

By Notification No. L. 12012/133/74/LR/III dated April 23, 1975, Government of India, Ministry of Labour referred the following matter of dispute to this Tribunal for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 14 of 1947):

## THE SCHEDULE

"Whether the action of the management of the Punjab National Bank in transferring Shri P. N. Sachin, clerk from Nayaganj Branch, Kanpur as Special Assistant to Rampur is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?"

Summons were issued to both the parties and were duly served on them. Parties filed their written statements and rejoinders. When the case was taken up for hearing on 29-9-75 an application was received from the workman concerned that he has accepted the offer for posting him as Special Assistant at P.O. Oral, hence there remains no dispute with the employers and the case be closed. In the circumstances no further relief can be given to the workman concerned from the matter raised in the Reference Order. The award is made accordingly.

26-9-75

K. N. SRIVASTAVA, Presiding Officer.

[No. L. 12012/133/74-LR/III]

**S.O. 5342.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 29th November, 1975.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT.

INDUSTRIAL TRIBUNAL, DELHI

PRESENT:

Shri D. D. Gupta, Central Govt., Industrial Tribunal, Delhi.

C.G.I.D. No. 52 of 1975

BETWEEN

The management of Central Bank of India, through their Zonal Manager, Zonal Office, Parliament Street, New Delhi.

AND

Their workmen as represented by the Central Bank Employees Union, Central Bank Building, Chandni Chowk, Delhi.

Shri S. C. Khattar—for the management.

Shri Tara Chand Gupta—for the workman.

## AWARD

The Central Govt. on being satisfied that an industrial dispute existed between the aforesaid parties has referred

the same for adjudication to this Tribunal by its Order No. L. 12012/71/75/DII/A dated the 4th August, 1975 with the following terms of reference:—

"Whether the action of the management of the Central Bank of India, New Delhi in terminating the services of Shri Virendra Kumar, Part-time pass book writer with effect from the 9th July, 1974 and if not appointing the said workman as full time clerk to what relief is the said workman entitled?"

2. When the case came up today for hearing before me, a memorandum of settlement was jointly filed by Shri S. C. Khattar on behalf of the management, and by Shri Tara Chand Gupta on behalf of the workman. Both the above-named representatives of the parties verify and admit the terms of settlement Annexure 'A' and seek an award of terms thereof. I, therefore, pass an award in terms of settlement Annexure 'A' which shall form a part of the award.

24th November, 1975.

D. D. GUPTA, Central Govt,  
Industrial Tribunal, Delhi.

## ANNEXURE 'A'

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT.

INDUSTRIAL TRIBUNAL, DELHI

C.G.I.D. No. 52 of 1975

In the matter of an Industrial dispute

BETWEEN

The Management of Central Bank of India and their workmen.

MAY IT PLEASE THE HONOURABLE TRIBUNAL :

The parties to the above reference have arrived at an amicable settlement in the matter of above industrial dispute. The terms of the settlement are set out below:—

## TERMS OF SETTLEMENT

1. Shri Virendra Kumar shall be taken-up in the employment of the Bank as a fresh appointee under the designation of a full-time clerk-cum-pass book writer with effect from the date he reports for duty to the Divisional Manager at Meerut.

2. Shri Virendra Kumar shall not be entitled to any pay and allowances or any other monetary or non-monetary benefits/priveleges from the date his services as a part-time pass book writer were terminated on 9th July, 1974 till the date he reports for duty at Meerut.

The parties, therefore, pray that this Hon'ble Tribunal may be pleased to make an award in terms of the above settlement.

For and on behalf of  
Central Bank Employees  
Union, Delhi

For an on behalf of  
the Central Bank of  
India, New Delhi.  
(Management).

1. B. P. Upadhyia President of  
Central Bank Employees  
Union, Delhi.

M. K. Venkateshwaran  
Asstt. Zonal Manager,  
Central Bank of India,  
New Delhi.

2. Tara Chand Gupta  
General Secretary,  
Central Bank Employees Union,  
Delhi.

Witness.

(S. C. Khattar)

Delhi : 24th November, 1975

[No. L-12012/71/75-DII/A]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

## प्रति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1975

का० बा० 5343.—निष्कास्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 55 की उपधारा (3) द्वारा मुझे महा अभिरक्षक के रूप में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं इस विभाग की अधिसूचना संख्या 1 (30)/विशेष सेल/75-एस० एस०-II दिनांक 12 नवम्बर, 1975 द्वारा राजस्थान राज्य के लिए नियुक्त उप महा अभिरक्षक, श्री शेर सिंह को महा अभिरक्षक की निम्नलिखित शक्तियाँ सौंपता हूँ :—

- (1) अधिनियम की धारा 24 और 27 के अन्तर्गत आने वाली शक्तियाँ।
- (2) अधिनियम की धारा 10(2)(0) के अन्तर्गत किसी निष्कास्त सम्पत्ति के हस्तांतरण को अनुमोदित करने की शक्तियाँ।
- (3) निष्कास्त सम्पत्ति प्रशासन (केन्द्रीय), नियमावली, 1950 के नियम 30-क के अन्तर्गत मामलों को हस्तांतरित करने की शक्तियाँ।

[संख्या 1(30)/विशेष सेल/75-एस० एस०-II]

चि० न० दूबे, महा अभिरक्षक

## MINISTRY OF SUPPLY &amp; REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 26th November, 1975

S.O. 5343.—In exercise of the powers conferred on me as Custodian General by sub-Section (3) of Section 55 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950) I hereby delegate to Shri Sher Singh, Deputy Custodian General for the State of Rajasthan appointed vide this Department's Notification No. 1(30)/Spl. Cell/75-SS. II dated the 12th November, 1975, the following powers of the Custodian General :

- (1) Powers under Section 24 and 27 of the Act.
- (2) Powers of approval of transfer of any evacuee property under Section 10(2)(0) of the Act.
- (3) Powers of transfer of cases under Rule 30—A of the Administration of Evacuee Property (Central) Rules, 1950.

[No. 1(30)/Spl. Cell/75-SS. II]

B. N. DUBEY, Custodian General.

## वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1975

का. आ. 5344.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्यात निरीक्षण परिषद् अंशवाची भविष्य निधि नियमों में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम निर्यात निरीक्षण परिषद् अंशवाची भविष्य निधि (संशोधन) नियम, 1975 है।

2. निर्यात निरीक्षण परिषद् अंशवाची भविष्य निधि नियम, 1969 के नियम 1 में, उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) ये 21 जून 1969 को प्रवृत्त होंगे।”

[सं. 1/20/73-नि. नि. तथा नि. उ.]

कै. वी. बालसुब्रामण्यम, उप-निदेशक

## MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 13th December, 1975

S.O. 5344.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export Inspection Council Contributory Provident Fund Rules, 1969, namely :—

1. These rules may be called the Export Inspection Council Contributory Provident Fund (Amendment) Rules, 1975.

2. In rule 1 of the Export Inspection Council Contributory Provident Fund Rules, 1969, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(2) They shall come into force on the 21st June, 1969.”

[No. 1/20/73/E.I &amp; E.P.]

K. V. BALASUBRAMANIAM, Dy. Director.

